राष्ट्रीय हिंदी मासिक पत्रिका

तेजस बिन्दु

मूल्य ₹50/-

वर्ष-03, अंक-10, मई-2026

RNI No.: UPHIN/2023/87359

लालू यादव की डोर से बंधी है सम्राट की सत्ता

पत्रकार एकता फोरम

संस्थापक

डॉक्टर तेजस यादव

RNI No.: UPHIN/2023/87359

तेजस बिन्दु

हिन्दी मासिक पत्रिका मूल्य : ₹50/-

वर्ष:03, अंक-10, मई-2026

संपादक
आरती यादव

सह संपादक
निशा सिंह

प्रबन्ध संपादक
दुर्गावती देवी

विधिक सलाहकार
मानती यादव

ब्यूरो चीफ बिहार
प्रीत कुमार यादव

संवाददाता
साधना देवी, गीता देवी

मैगजीन लेआउट
ZENTAL MEDIA HOUSE
8881544447

तेजस बिन्दु के लिए स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, आरती यादव द्वारा इशिता प्रिन्टर्स, 168/8, हेवेट रोड़, हुसैनगंज चौराहा, लखनऊ (उ०प्र०)-226001 से मुद्रित एवं 251 ग्रा० लटेरा पो०-धोरहरा डुमरियागंज, सिद्धार्थनगर (उ०प्र०)-272189 से प्रकाशित।

रजिस्टर्ड कार्यालय
251 ग्रा० लटेरा पो०-धोरहरा डुमरियागंज,
सिद्धार्थनगर (उ०प्र०)-272189

Mob. 9838595489
E-mail:tejasips89@gmail.com

पत्रिका से संबंधित समस्त वाद विवादों का न्याय क्षेत्र सिद्धार्थनगर, उ०प्र० न्यायालय होगा।

सभी पद अवैतनिक है।

इस अंक में

लालू यादव की डोर से बंधी है सम्राट की सत्ता

सतना जिले में पत्रकारिता का गिरता स्तर:
कुंठित मानसिकता और भगोड़े दलालों का शिकार

बेगूसराय में पत्रकार के साथ मारपीट...

कॉलेजियम पर कोलाहल

नहीं रहे शिक्षा को आगे बढ़ाने वाले कृष्ण पाल सिंह

देश पर बढ़ता कर्ज

भारत सरकार पर बढ़ता हुआ कर्जा (Debt) और विदेशी कर्ज देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। हालिया आंकड़ों के अनुसार, यह कर्जा चिंता का विषय बन सकता है यदि इसका उपयोग उत्पादक कार्यों के बजाय केवल उपभोग के लिए किया जाए।

देश पर बढ़ते कर्ज से संबंधित मुख्य बिंदुः

प्रति व्यक्ति कर्जः एक अनुमान के अनुसार, भारत के हर नागरिक पर लगभग 42,700 रुपये का सरकारी कर्ज का बोझ है।

विदेशी कर्ज में वृद्धिः 2014 के बाद से भारत पर विदेशी कर्जा काफी बढ़ा है।

कर्ज के कारणः सरकार पर बढ़ते कर्ज के पीछे विकास कार्यों, बुनियादी ढांचे (Infrastructure) के निर्माण और सरकारी योजनाओं पर होने वाला भारी खर्च है।

कर्ज बनाम GDP: कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि कर्ज लेकर देश की अर्थव्यवस्था (GDP) को बढ़ाया जा रहा है. तो यह सकारात्मक संकेत हो सकता है।

सतना जिले में पत्रकारिता का गिरता स्तर:
कुंठित मानसिकता और भगोड़े दलालों का शिकार

सतना जिले में पत्रकारिता का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। कुछ मंद बुद्धि वाले तथाकथित पत्रकार समाज, देश, अर्थव्यवस्था या जनहित की खबरों से कोसों दूर रहते हैं। इनका एकमात्र उद्देश्य उच्च पदस्थ व्यक्तियों को बदनाम करना और विवादित खबरें फैलाना बन चुका है। यह ओछी पत्रकारिता न केवल पत्रकारिता के सिद्धांतों का अपमान है, बल्कि समाज को गुमराह करने वाला षड्यंत्र भी है। ओछी मानसिकता से ग्रस्त पत्रकार: जनहित भूलकर बदनामी का धंधासतना के कुछ पत्रकारों की मानसिकता पूरी तरह ओछी हो चुकी है। ये लोग जनहित की बजाय सनसनीखेज और विवादित सामग्री पर ध्यान केंद्रित करते हैं। समाजसेवियों, अधिकारियों या अन्य उच्च व्यक्तियों को निशाना बनाकर ये अपनी 'पत्रकारिता' का प्रमाण देते फिरते हैं। वास्तव में, इनका पत्रकारिता से कोई लेना-देना नहीं। ये खबरें चलाकर अपनी रोटियां सेंकते हैं, बिना किसी तथ्य या जिम्मेदारी के। स्थानीय स्तर पर ऐसी खबरें बढ़ रही हैं जो केवल बदनामी फैलाती हैं, न कि समस्याओं का समाधान।उदाहरण के तौर पर, हालिया घटनाओं में देखा गया है कि कुछ स्थानीय न्यूज पोर्टल्स और सोशल मीडिया हैंडल्स पर बिना सत्यापन के अफवाहें फैलाई जा रही हैं। ये पत्रकार जनहित मुद्दों जैसे बेरोजगारी, स्वास्थ्य सेवाएं या कानून-व्यवस्था पर चुप्पी साधे रहते हैं, लेकिन किसी अधिकारी की छवि खराब करने का कोई मौका नहीं छोड़ते।भगोड़े दलालों का खेल: फुटबॉल की तरह लुढ़कते 'पत्रकार'सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इन षड्यंत्रों में शामिल लोग कौन हैं? ये न तो सच्चे पत्रकार हैं, न ही समाजसेवी। ये बाहर से भगाए हुए दलाल हैं, जिनका कोई वजूद नहीं। फुटबॉल की तरह ये जहां चाय-पान के टुकड़े या कोई फायदा मिले, वहीं लुढ़क जाते हैं। सतना जिले में ऐसे तत्वों की घुसपैठ बढ़ी है, जो पैसे या स्वार्थ के लिए झूठी खबरें फैलाते हैं। इनका कोई स्थायी ठिकाना या पहचान नहीं। ये सोशल मीडिया पर अज्ञात खाते चलाते हैं और स्थानीय मुद्दों को तोड़-मरोड़कर पेश करते हैं। जिले के सम्मानित पत्रकारों और समाजसेवियों ने इन पर चिंता जताई है। एक स्थानीय वरिष्ठ पत्रकार ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, "ये दलाल पत्रकारिता को बदनाम कर रहे हैं। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है। "समाज पर असर: विश्वास का हनन और जनहित की उपेक्षाइस गिरते स्तर का सबसे बुरा असर समाज पर पड़ रहा है। लोग सच्ची खबरों और अफवाहों में फंस जाते हैं, जिससे सामाजिक सद्भाव प्रभावित होता है। सतना जैसे जिले में जहां कानून-व्यवस्था और विकास के मुद्दे गंभीर हैं, वहां ऐसी पत्रकारिता विकास को पटरी से उतार रही है। अर्थव्यवस्था और जनहित की अनदेखी हो रही है।जिला प्रशासन और प्रेस काउंसिल को ऐसे तत्वों पर नजर रखनी चाहिए। सतना के नागरिकों को भी सतर्क रहना होगा और सत्यापित स्रोतों से ही खबरें ग्रहण करनी चाहिए।समाजसेवी संगठनों ने की मांग: ऐसे फर्जी पत्रकारों पर कानूनी कार्रवाई हो और सच्ची पत्रकारिता को बढ़ावा दिया जाए।

लोकतंत्र का चौथा स्तंभ डगमगाता क्यों? पत्रकारिता के गिरते स्तर पर बड़ा सवाल

- आरपी यादव / बिहार ब्यूरो तेजस बिंदु

बिहार: पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है एक ऐसा स्तंभ, जो सत्ता से सवाल करता है, आम जनता की आवाज बनता है और समाज के दबे-कुचले, वंचित वर्गों की समस्याओं को शासन-प्रशासन तक पहुंचाता है। लेकिन आज के दौर में यही स्तंभ खुद सवालों के घेरे में खड़ा नजर आ रहा है। कभी पत्रकारिता समाज सेवा का सबसे सशक्त माध्यम हुआ करती थी। गांव के गरीब किसान, मजदूर, छात्र और बेरोजगार युवा अपनी समस्याओं को सीधे सत्ता तक नहीं पहुंचा पाते थे, लेकिन एक पत्रकार उनकी आवाज बनकर उन्हें अखबार और मीडिया के माध्यम से उठाता था। यही कारण था कि जब कोई खबर छपती थी, तो प्रशासन की नींद टूटती थी और कार्रवाई होती थी।लेकिन वर्तमान समय में तस्वीर तेजी से बदल रही है।

अब कई जगहों पर यह देखने को मिल रहा है कि पत्रकारिता निष्पक्षता से हटकर सत्ता के साथ खड़ी नजर आती है। पत्रकार और प्रशासन के बीच

बढ़ती नजदीकियां पत्रकारिता की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रही हैं। जहां पहले पत्रकार सवाल करता था, अब वही कई बार सत्ता का पक्ष प्रस्तुत करता दिखाई देता है।यह स्थिति बेहद चिंताजनक है। क्योंकि अगर पत्रकार ही सत्ता से मिल जाए, तो फिर जनता की आवाज कौन उठाएगा? कौन पूछेगा कि योजनाओं का लाभ गरीब तक क्यों नहीं पहुंच रहा? कौन उजागर करेगा भ्रष्टाचार और लापरवाही को?पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्ता की गलतियों को सामने लाना और समाज के हित में काम करना है। यदि यह उद्देश्य ही खो गया, तो लोकतंत्र की पूरी संरचना कमजोर हो जाएगी। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका ये तीनों स्तंभ तभी संतुलित रहते हैं, जब चौथा स्तंभ यानी मीडिया स्वतंत्र और निष्पक्ष रहता है।इतिहास गवाह है कि जब-जब अन्य तीनों स्तंभ कमजोर पड़े हैं, तब पत्रकारिता ने ही सच्चाई को उजागर कर व्यवस्था को आईना दिखाया है। लेकिन अगर चौथा स्तंभ ही कमजोर हो जाए, तो लोकतंत्र की नींव हिल सकती है।आज जरूरत है कि पत्रकारिता अपने मूल सिद्धांतों की ओर लौटे सच्चाई, निष्पक्षता और जनहित। पत्रकारों को यह समझना होगा कि उनका काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि समाज को दिशा देना भी है।अगर पत्रकारिता मजबूत होगी, तो लोकतंत्र मजबूत होगा। और अगर पत्रकारिता कमजोर हुई, तो इसका असर पूरे देश और समाज पर पड़ेगा।

यूरिक एसिड का स्तर कितना होना चाहिए? उम्र के हिसाब से चार्ट देखें वयस्क पुरुष: 4.0-8.5 mg/dL या 0.24-0.51 mmol/L वयस्क महिला: 2.7-7.3 mg/dL या 0.16-0.43 mmol/L बुजुर्ग: मामूली वृद्धि हो सकती है। बच्चा: 2.5-5.5 mg/dL या 0.12-0.32 mmol/L नवजात: 2.0-6.2 mg/dL महिलाओं में यूरिक एसिड का स्तर कितना होना चाहिए? | Uric acid level in women महिलाओं में सामान्य स्तर 1.5 से 6.0 mg/dL है। महिलाओं में जब यूरिक एसिड का स्तर 9.5 मिलीग्राम/डीएल तक पहुंच जाता है, तो यह शरीर को और अधिक नुकसान पहुंचा सकता है। यूरिक एसिड के इन बढ़े हुए स्तरों से गुर्दे की विफलता, किडनी और ब्लड प्रेशर और मधुमेह हो सकता है। यूरिक एसिड ऐसे करें कंट्रोल | Uric Acid Control Tips फल और सब्जियों का सेवन करें। डाइट में प्यूरीन युक्त खाद्य पदार्थों से परहेज करें। पानी ज्यादा पिएं। रेड मीट, सीफूड से परहेज करें। सोया, पनीर, दाल जैसे प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों से परहेज करें। खाने में लो फैट फूड का इस्तेमाल करें। उच्च वसा वाले खाद्य पदार्थ समस्या को बढ़ा सकते हैं। रोजाना आधा घंटा टहलें या व्यायाम करें। यूरिक एसिड एक शरीर में बनने वाला जहर है जो हर किसी के शरीर में उत्पन्न होता है। यूरिक एसिड का बढ़ना कोई समस्या नहीं है, लेकिन इससे छुटकारा न मिलना शरीर को बीमार कर देता है। डाइट में प्यूरीन युक्त फूड्स पदार्थ जैसे रेड मीट, सीफूड, कुछ मछली, पोल्ट्री उत्पाद और मीठे खाद्य पदार्थों का सेवन करने से शरीर में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ जाता है। यूरिक एसिड बढ़ने के बाद इसके लक्षण शरीर में दिखने लगते हैं। यूरिक एसिड के लक्षणों में जोड़ों में दर्द और सूजन, पैर की उंगलियों में सूजन, जोड़ों में गांठ और उंगलियों में दर्द शामिल हैं। ब्लड में कितना होना चाहिए यूरिक एसिड ? | Uric acid Level in Blood मेडिकल न्यूज टुडे के अनुसार, पुरुषों और महिलाओं में यूरिक एसिड का स्तर अलग-अलग होता है। महिलाओं में यूरिक एसिड का स्तर 2.4 से 6.0 mg/dL की सीमा में सामान्य माना जाता है। अगर महिलाओं में यूरिक एसिड 6.0 mg/dL से कम है तो यह खतरनाक नहीं है। हर इंसान में कम या ज्यादा यूरिक एसिड बनता है, जिसे किडनी फिल्टर करके शरीर से बाहर निकाल देती है। खतरा तब बढ़ जाता है जब यह जहर शरीर में जमा होने लगता है।

डॉ. निशा सिंह, लखनऊ

बेगूसराय में पत्रकार के साथ मारपीट, मोबाइल और प्रेस कार्ड छीनने का आरोप

बेगूसराय, बिहार

जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र में एक पत्रकार के साथ मारपीट और सामान छीनने का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़ित पत्रकार प्रीत कुमार यादव उर्फ आर.पी. यादव ने नौला पिकेट प्रभारी अकरम खान पर न्यूज़ कवरेज के दौरान अभद्र व्यवहार, मारपीट और उनका मोबाइल, प्रेस कार्ड, गमछा एवं मोटरसाइकिल छीन लेने का आरोप लगाया है।प्राप्त जानकारी के अनुसार, 24 अक्टूबर 2025 की शाम करीब 4 बजे पत्रकार प्रीत कुमार यादव भीठसारी पंचायत के भीत गांव से गुजर रहे थे। इसी दौरान कुछ महिलाएं और ग्रामीण पिकेट प्रभारी के कथित व्यवहार से नाराज होकर सड़क जाम कर प्रशासनिक अधिकारियों को बुलाने की मांग कर रहे थे।बताया जाता है कि सूचना मिलते ही पत्रकार ने डीएसपी तेघड़ा को फोन कर स्थिति से अवगत कराया और मौके पर मौजूद लोगों के कहने पर समाचार कवरेज करने लगे। इस दौरान वे ग्रामीणों और महिलाओं के बयान अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहे थे।इसी बीच आरोप है कि पिकेट प्रभारी अकरम खान ने उन्हें जबरन पकड़कर पिकेट पर ले जाया गया और वीडियो देखने के बहाने उनका मोबाइल, प्रेस कार्ड, गमछा और मोटरसाइकिल छीन लिया गया।

पत्रकार का आरोप है कि पिकेट पर उनके साथ मारपीट की गई, गाली-गलौज की गई और अभद्र व्यवहार किया गया।इतना ही नहीं, बाद में पत्रकार के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया। लगभग चार महीने बाद रिहा होने के बाद जब उन्होंने अपना सामान वापस मांगा, तो थाना स्तर पर भी उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला।पीड़ित का कहना है कि मामले के जांच अधिकारी ने भी स्वीकार किया कि कई बार मोबाइल के संबंध में पूछे जाने के बावजूद संबंधित अधिकारी द्वारा मोबाइल उपलब्ध नहीं कराया गया।

वहीं, सीजर लिस्ट में भी मोबाइल, प्रेस कार्ड और अन्य सामान का कोई उल्लेख नहीं है, जिससे मामला और संदिग्ध हो जाता है।हालांकि, पत्रकार की मोटरसाइकिल बाद में उनके परिजनों को वापस कर दी गई, लेकिन मोबाइल अब तक नहीं लौटाया गया है। आरोप है कि मोबाइल देने के नाम पर कागजात लेने के बाद भी उसे वापस नहीं किया गया और अब यह कहा जा रहा है कि मोबाइल लिया ही नहीं गया था।पत्रकार ने इस पूरे मामले को प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला बताते हुए पुलिस अधीक्षक से निष्पक्ष जांच और दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

लालू यादव की डोर से बंधी है सम्राट की सत्ता

राजद का आधार कमजोर हुआ तो नीतीश की तरह चौधरी को भी निपटा देगी भाजपा अब बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं। वे कोईरी जाति से आते हैं और उनसे पहले सतीश प्रसाद सिंह भी मुख्यमंत्री बने थे, जो इसी जाति के थे। मतलब सम्राट चौधरी दूसरे कोईरी मुख्यमंत्री हैं। सतीश प्रसाद सिंह की भी सत्ता की डोर यादव से बंधी थी और सम्राट की सत्ता की डोर भी यादव से बंधी है। बस नेता का नाम बदल गया है और राजनीतिक परिस्थितियां बदल गयी हैं। सतीश प्रसाद सिंह बीपी मंडल की राजनीतिक ताकत की उपज थे और सम्राट चौधरी लालू यादव की राजनीतिक ताकत की उपज हैं। हम राजद, जदयू या हम वाले सम्राट चौधरी की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि भाजपा वाले सम्राट की बात कर रहे हैं । लालू यादव और उनकी पार्टी राजद का राजनीतिक आधार मजबूत है। इसलिए सम्राट को भाजपा ने मुख्यमंत्री बनाया है। भाजपा का मानना है कि लालू यादव के मजबूत आधार से मुकाबले के लिए उसी जाति वर्ग की बड़ी आबादी वाला वोट समूह चाहिए।

इस मानक पर सम्राट चौधरी अनुकूल बैठ रहे हैं। हम आते हैं 2020 के विधान सभा चुनाव परिणाम पर। 2020 में भाजपा के 74 विधायक थे, जबकि नीतीश कुमार के पास मात्र 43 विधायक थे। उस समय जदयू में कोईरी-कुर्मी विधायकों की संख्या मात्र 11 थी। इसके बावजूद भाजपा ने नीतीश कुमार का नेतृत्व स्वीकार किया और ढोया। उसकी वजह थी कि विधान सभा में राजद विधायकों की संख्या 75 थी। इसका मतलब यह है कि राजद मजबूत था तो नीतीश कुमार भी मजबूत थे, भले उनके विधायकों की संख्या मात्र 43 थी। इस संख्या बल के गणित में नीतीश कुमार के पास डोल-पत्ता खेलने यानी पलटी मारने का पूरा

विकल्प मौजूद था। इसलिए भाजपा नतमस्तक थी। अब आते हैं 2025 में। 2025 के विधान सभा चुनाव परिणाम में भाजपा विधायकों की संख्या 89 थी और जदयू विधायकों की संख्या 85 थी। इस बार जदयू में कोईरी-कुर्मी विधायकों की संख्या 23 है। इसके बावजूद इस कार्यकाल में नीतीश कुमार सौ दिन भी चैन से कुर्सी पर बैठ नहीं पाये थे कि भाजपा ने विदाई की पटकथा बांच दी। राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाकर उनकी विदाई तय कर दी। वजह थी कि लालू यादव के विधायकों की संख्या 25 पर सिमट जाना। लालू यादव कमजोर हुए तो नीतीश कुमार के पास डोल-पत्ता खेलने का अवसर भी समाप्त हो गया। इस अनुकूल माहौल में भाजपा ने नीतीश को धकिया दिया। स्पष्ट शब्दों में कहें तो विधान सभा में लालू यादव कमजोर हुए तो नीतीश नकारा हो गये। अब यही खतरा सम्राट चौधरी के लिए है। नीतीश के साथ भाजपा की प्रतिस्पर्धा विधान सभा में संख्या पर केंद्रित थी। इसलिए लालू यादव का संख्या बल कमजोर हुआ तो नीतीश को भाजपा ने निपटा दिया।

इसके विपरीत भाजपा के लिए सम्राट आंतरिक मामला हैं और नया खेल आधार वोट पर केंद्रित है। लालू यादव को 2020 और 2025 के विधान सभा चुनाव में लगभग बराबर वोट आया था 23 प्रतिशत। दोनों चुनावों में राजद उम्मीदवार की संख्या भी लगभग बराबर। एकाध कम या अधिक। मतलब भाजपा फ्री बिजली, पेंशन राशि में वृद्धि और दस हजरिया नोट फा ॅर वोट स्कीम के बावजूद लालू यादव का आधार वोट कम नहीं कर पायी। इसलिए नये आधार वोट को साधने के लिए सम्राट चौधरी को सूली पर चढ़ाया है। सम्राट की उपयोगिता तभी तक है, जब तक लालू यादव का आधार मजबूत है। जिस दिन लालू यादव का आधार वोट कमजोर हुआ, उसी दिन भाजपा सम्राट चौधरी को निपटा देगी, सत्ता से बेदखल कर देगी। यही सम्राट के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। नीतीश कुमार लालू यादव को विधान सभा में संख्या बल में कमजोर करके खुद तिरोहित हो गये। लालू यादव के आधार वोट को कमजोर करने की कोशिश करने में सम्राट सफल हुए तो नीतीश कुमार की तरह उन्हें भी उच्च सदन की राह दिखा दी जाएगी। सम्राट का कार्यकाल तभी दीर्घकालीक होगा, जब लालू यादव और उनकी ताकत भाजपा को बेचैन किये रहेगी। जिस दिन भाजपा के अंदर लालू यादव का डर खत्म हो जाएगा, उस दिन भाजपा ने लिए सम्राट भी अप्रासंगिक हो जाएंगे। मतलब सम्राट चौधरी की सत्ता की डोर राजद से बंधी है और इस नाजुक यथार्थ को सम्राट चौधरी अनदेखी नहीं कर सकते हैं।

कॉलेजियम पर कोलाहल

केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने पिछले दिनों अहमदाबाद में एक कार्यक्रम और उससे पहले उदयपुर में भावी कानूनी मुद्दों पर आयोजित कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए जजों की नियुक्ति के वर्तमान कॉलेजियम सिस्टम पर कुछ गंभीर सवाल उठाए। बाद में शिलांग में आयोजित एक कार्यक्रम में कानून मंत्री ने अपनी बातों को दोहराया। कानून मंत्री द्वारा बार-बार इस बारे में सवाल उठाए जाने से ये लगता है कि केंद्र सरकार जजों की नियुक्ति की वर्तमान व्यवस्था की खामियों को लेकर गंभीर है और इस पर बहस कराना और मुमकिन है कि इस व्यवस्था में सुधार करना या इसे बदलने की सोच रही है।

क्या है कॉलेजियम सिस्टम ?

कॉलेजियम सिस्टम हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति की व्यवस्था है। ये व्यवस्था संविधान से नहीं आई है और न ही इसके लिए संसद में कोई कानून पास किया है। ये व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के दो फैसलों (जजेज केस) से आई है। इसके मुताबिक,

सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और जजों के ट्रांसफर के फैसले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और चार अन्य सबसे सीनियर जजों का समूह करता है।

हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और दो सबसे सीनियर जजों का समूह करता है।

हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति की सिफारिश उस हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और दो सबसे सीनियर जजों का समूह करता है। इन सिफारिशों की समीक्षा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और दो सबसे सीनियर जज करते हैं।

जजों के समूह यानी कॉलेजियम द्वारा की गई सिफारिशों को मानना सरकार (राष्ट्रपति) के लिए अनिवार्य होता है। सरकार चाहे तो कॉलेजियम से एक बार ये अनुरोध कर सकती है कि वह अपनी सिफारिश पर पुनर्विचार करे, पुनावच लेकिन कॉलेजियम ने वही सिफारिश फिर से भेज दी, तो सरकार के लिए उसे मंजूर करना जरूरी होता है। यानी कॉलेजियम सिस्टम में सरकार की भूमिका सलाह देने या अपनी असहमति जताने तक सीमित है। इसे मानना या न मानना जजों के समूह के हाथ में है।

संविधान में उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति में राष्ट्रपति यानी कार्यपालिका (सरकार) को प्राथमिकता दी गई है। संविधान के अनुच्छेद 124 (2) के मुताबिक 'उच्चतम न्यायालय के और राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के पश्चात, जिनसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए परामर्श करना आवश्यक सम्झे, राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा.' संवैधानिक भाषा में इस अनुच्छेद में जो लिखा है, उसका मतलब है कि राष्ट्रपति जजों की नियुक्त के लिए जजों से परामर्श (Consultation) ले सकता है। इसमें राष्ट्रपति की सर्वोच्चता निहित है।

1980 से लेकर 90 के दशक की शुरुआत में देश की राजनीति की सामाजिक संरचना तेजी से बदल रही थी। खासकर पिछड़े वर्ग की लोक सभा और विधान सभाओं में संख्या बढ़ रही थी
और उसी के साथ उच्च जातियों की हिस्सेदारी घट रही है। इस बीच, वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की सिफारिशों के मुताबिक सरकारी नौकरियों में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू कर दिया। इससे सवर्ण तबकों के इलीट घबरा गए। उन्हें लगा कि संसद-विधानसभाओं, मंत्रिमंडलों के बाद अगर नौकरशाही में भी उनका दबदबा टूट गया तो क्या होगा। इसे देखते हुए उन्होंने जजों की नियुक्ति की ऐसी व्यवस्था बनाई जो संसद और सरकार से पूरी तरह आजाद है और जिसमें सवर्ण वर्चस्व बनाए रखने में कोई बाधा नहीं हो. इस तरह वर्चस्ववादी वर्ग ने सत्ता के एक अंग को पूरी तरह अपने नियंत्रण में ले लिया।

1980 से लेकर 90 के दशक की शुरुआत में देश की राजनीति की सामाजिक संरचना तेजी से बदल रही थी। खासकर पिछड़े वर्ग की लोक सभा और विधान सभाओं में संख्या बढ़ रही थी और उसी के साथ उच्च जातियों की हिस्सेदारी घट रही है। इस बीच, वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की सिफारिशों के मुताबिक सरकारी नौकरियों में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू कर दिया। इससे सवर्ण तबकों के इलीट घबरा गए। उन्हें लगा कि संसद-विधानसभाओं, मंत्रिमंडलों के बाद अगर नौकरशाही में भी उनका दबदबा टूट गया तो क्या होगा। इसे देखते हुए उन्होंने जजों की नियुक्ति की ऐसी व्यवस्था बनाई जो संसद और सरकार से पूरी तरह आजाद है और जिसमें सवर्ण वर्चस्व बनाए रखने में कोई बाधा नहीं हो, इस तरह वर्चस्ववादी वर्ग ने सत्ता के एक अंग को पूरी तरह अपने नियंत्रण में ले लिया।

1993 में कॉलेजियम सिस्टम का आना क्यों महत्वपूर्ण है सवाल उठता है कि कॉलेजियम सिस्टम को इससे पहले क्यों नहीं लाया गया। दरअसल इसके कारणों को समकालीन राजनीति के समाजशास्त्र से समझा जा सकता है। आजादी के बाद के पहले बीस साल लगभग पूरी तरह कांग्रेस के थे। 1967 में पहली बार उसे तब झटका लगा जब विधानसभा चुनावों के बाद 9 राज्यों में गैर-कांग्रेस दलों की मिली-जुली सरकार बन गई। इन सरकारों में उन जातियों का प्रतिनिधित्व भी था, जिन्हें समेटकर चलने में कांग्रेस विफल साबित हुई थी। इनमें मझौली और अपेक्षाकृत निचली जातियों के संगठन और नेता भी थे।

1977, इस प्रक्रिया का दूसरा अहम पड़ाव था, जब पहली बार केंद्र में कांग्रेस हार गई और जनता पार्टी की सरकार बनी. इस सरकार में पिछड़ी जातियों के कई प्रमुख नेता थे। इसी दौरान दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग यानी मंडल कमीशन का गठन हुआ। हालांकि उसकी रिपोर्ट आने तक जनता पार्टी की सरकार जा चुकी थी। 1977 में ही उत्तर भारत के दो सबसे महत्वपूर्ण राज्यों उत्तर प्रदेश और बिहार में ओबीसी समुदायों के दो नेता राम नरेश यादव और कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने और दोनों ने अपने अपने राज्यों में पहली बार पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण लागू कर दिया।

ओबीसी का दबदबा राष्ट्रीय राजनीति में पहली बार 1989 में ढंग से दिखा जब कई ओबीसी नेता उभरकर सामने आए और वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। 1990 का दशक राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक खींचतान के लिए भी जाना जाता है। ये दिलचस्प है कि जिस समय लोकतंत्र का समाज के निचले और मझोले तबकों में विस्तार हो रहा था और वंचित जातियों के लोग राजनीति और राजकाज में हिस्सेदारी लेने की कोशिश कर रहे थे तो अकादमिक संस्थानों में बैठे विद्वान इसे भारतीय लोकतंत्र का संकट बता रहे थे। ये शायद इसलिए भी हुआ क्योंकि अकादमिक संस्थानों में आम तौर पर वंचित स्वर नहीं हैं या कम हैं।

बेगूसराय में कांग्रेस को मिला नया चेहरा शिव प्रकाश गरीब दास बने जिलाध्यक्ष

संघर्ष की, सादगी की, और जिद की। इसी मिट्टी से उठे एक ऐसे किरदार की कहानी है, जिसका नाम है अवधेश कुमार राय।संघर्ष से शुरुआत हुई साल था लगभग 1952। एक साधारण परिवार में जन्मे अवधेश कुमार राय ने बचपन से ही गरीबी, असमानता और अन्याय को बहुत करीब से देखा। गाँव की पगडंडियों पर चलते-चलते उनके भीतर एक सवाल हमेशा उठता "क्या गरीब हमेशा ऐसे ही जीने को मजबूर रहेंगे?"यही सवाल धीरे-धीरे उनके जीवन का उद्देश्य बन गया। राजनीति में कदम और पहचान बनती गई समय बदला, और उन्होंने जुड़ाव किया भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से एक ऐसी विचारधारा से, जो गरीबों और मजदूरों की आवाज बनती है।1990 से 2000 तक, बछवारा विधानसभा क्षेत्र ने उन्हें अपना प्रतिनिधि चुना विधायक के रुप में। यह सिर्फ जीत नहीं थी, बल्कि जनता का विश्वास था

एक ऐसे नेता पर, जो उनके बीच का ही था।लेकिन राजनीति का रास्ता कभी सीधा नहीं होता...हार जो जीत की नींव बनी साल 2000 का चुनाव आया। मुकाबला कड़ा था। नतीजा आया सिर्फ 464 वोटों से हार।कई लोग टूट जाते, लेकिन अवधेश कुमार राय नहीं।उन्होंने इसे अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत माना।संघर्ष जारी रहा संघर्ष ही बल होता है साल 2005 के दोनों चुनावों में वे दूसरे स्थान पर रहे। हर हार के बाद वे और मजबूती से जनता के बीच लौटे गाँव-गाँव, खेत-खलिहान, मजदूरों की चौपाल, गरीबों के आँगन...लोग कहते थे

"नेता नहीं, अपना आदमी है ये।"वापसी और वो भी दमदार से 2010 में, संयुक्त वाम मोर्चे के समर्थन से उन्होंने बछवारा सीट फिर से जीत ली।और उस समय वे पूरे बिहार में एकमात्र CPI विधायक बने।यह सिर्फ व्यक्तिगत जीत नहीं थी

यह विचारधारा की जीत थी, संघर्ष की जीत थी।आज का दौर यह है कि बेगूसराय जिला का मजबूत चेहरासमय के साथ उनकी भूमिका और मजबूत होती गई।आज वे लगातार दूसरी बार जिला सचिव के पद पर हैं।उनकी पहचान सिर्फ एक नेता की नहीं, बल्कि गरीबों के हमदर्द की,संघर्ष के सिपाही की,और "संघर्ष का मसीहा की"के रूप में है।कोई भी मामला हो गरीबों का हक, मजदूरों की लड़ाई, या अन्याय के खिलाफ आवाज अवधेश कुमार राय हमेशा सबसे आगे खड़े मिलते हैं। उनकी असली सबसे बड़ी ताकत है उनकी भाषा और लोगों से जुड़ाव। वे भाषण नहीं देते दिल से बात करते हैं।वे राजनीति नहीं करते लड़ाई लड़ते हैं।एक नेता नहीं, एक कहानी जो 5 अप्रैल 2024 को मटिहानी, बेगूसराय की रैली में जब वे मंच पर खड़े थे, तो सिर्फ एक नेता नहीं बोल रहा था

बल्कि वो इंसान बोल रहा था जिसने अपनी पूरी जिंदगी गरीबों के लिए समर्पित कर दी।अंत में... वही बात अवधेश कुमार राय की संघर्ष कहानी हमें ये सिखाती है हार मायने नहीं रखती, अगर इरादे जिंदा हों।नेता वो नहीं जो कुर्सी पर बैठे, बल्कि वो है जो लोगों के दिल में रहे।

ग्राम रक्षा दल मुंगेर बिहार

मुंगेर की धरती पर जब साहस, संघर्ष और सेवा की मिसाल दी जाती है, तो एक नाम पूरे सम्मान के साथ लिया जाता है सपना भारती। यह सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि उन हजारों गरीब, असहाय और पीड़ित लोगों की आवाज है, जिन्हें समाज अक्सर नजरअंदाज कर देता है। मुंगेर जिला जिसके अंतर्गत मुंगेर सदर, हवेली खड़गपुर और तारापुर जैसे अनुमंडल, 9 प्रखंड और 19 पुलिस थाने आते हैं इन सभी क्षेत्रों में अगर किसी महिला ने अपनी अलग पहचान बनाई है, तो वह हैं सपना भारती। उन्होंने यह साबित कर दिया कि सच्ची सेवा के लिए किसी पद, शक्ति या पहचान की जरूरत नहीं होती, बल्कि जरूरी होता है अटूट जज्बा, ईमानदारी और लोगों के प्रति समर्पण।"लेडीज सिंघम" के नाम से मशहूर सपना भारती ने वर्ष 2015 से ग्राम रक्षा दल के माध्यम से जो संघर्ष शुरू किया, वह आज भी उसी मजबूती और जुनून के साथ जारी है।

गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याएं सुनना, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना और उनकी आवाज को प्रशासन तक पहुंचाना यह सब उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है।उन्होंने केवल काम नहीं किया, बल्कि एक आंदोलन खड़ा किया है। कभी सड़कों पर उतरकर आवाज बुलंद की, तो कभी अधिकारियों के दरवाजे खटखटाए हर बार अपने साथियों और समाज के हक के लिए डटकर खड़ी रहीं। थाना हो, प्रखंड कार्यालय या अनुमंडल हर जगह उनकी मौजूदगी लोगों के लिए उम्मीद की किरण बन चुकी है।सपना भारती ने यह भी दिखा दिया कि जब एक महिला ठान ले, तो वह पूरे सिस्टम को झकझोर सकती है। ग्राम रक्षा दल के सदस्यों के अधिकार, सम्मान और पहचान के लिए उनकी उठाई गई आवाज आज एक जनांदोलन का रूप ले चुकी है।आज जब बिहार सरकार ग्राम रक्षा दल के लिए प्रशिक्षण और नई योजनाएं शुरू कर रही है, तो सपना भारती और उनके जैसे हजारों

कर्मठ कार्यकर्ताओं को यह भरोसा मिला है कि उनकी वर्षों की मेहनत अब रंग लाने वाली है। यह सिर्फ एक सरकारी पहल नहीं, बल्कि उनके संघर्षों की पहली बड़ी जीत है। सपना भारती की कहानी हमें यह सिखाती है कि असली ताकत कुर्सी में नहीं, बल्कि सेवा भावना में होती है। वह आज भी बिना थके, बिना रुके और बिना किसी स्वार्थ के लोगों की सेवा में निरंतर जुटी हुई हैं। वह एक महिला नहीं, एक आंदोलन हैं।वह एक नाम नहीं, एक पहचान हैं। वह एक आवाज नहीं, बल्कि पूरे समाज की उम्मीद हैं।

नहीं रहे शिक्षा को आगे बढ़ाने वाले कृष्ण पाल सिंह

लंबी बीमारी के बाद हुआ निधन

सिद्धार्थ नगर। डुमरियागंज तहसील में शिक्षा को आगे बढ़ाने वाले कृष्णपाल सिंह नहीं रहे लंबी बीमारी के बाद लगभग 90 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया उनके निधन पर लोगों ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि शिक्षा को आगे बढ़ाने वाले कृष्णपाल सिंह का निधन होना अपूरणीय छती है। बताते चलें कि कृष्ण पाल सिंह जनता आदर्श इंटर कॉलेज गौरा बाजार, ललिता इंटर कॉलेज चौखड़ा बाजार, के प्रबंधक थे। बीच में उम्र अधिक हो जाने के कारण उनके पुत्र आनंद सिंह ललिता इंटर कॉलेज चौखड़ा बाजार तथा पीपल्सइंटर कॉलेज डुमरियागंज का प्रबंधन बन गए श्री सिंह का तबीयत ज्यादा खराब हो गया उन्हें लखनऊ में मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। उनका पार्थिव शरीर आते ही घर पर लंबी भीड़ लग गई लोग वहां पहुंचकर शोक व्यक्त करने लगे। उनका अंतिम संस्कार राप्ती नदी तट डुमरियागंज मैं किया गया जहां क्षेत्रीय सांसद जगदंबिका पाल पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह पूर्व प्रत्याशी इरफान मलिक पूर्व प्रत्याशी रामकुमार यादव विधायक अरुण वीर सिंह ठाकुर प्रसाद तिवारी अमरनाथ सिंह मनोज सिंह अरुण कुमार सिंह डॉ विनोद मिश्रा प्रधानाचार्य रुद्रपाल इंटर कॉलेज प्रधानाचार्य डुमरियागंज प्रधानाचार्य चौखड़ा प्रधानाचार्य गोरा बाजार स्टाफ के साथ जहां मौजूद थे वहीं तमाम राजनीतिक व्यक्ति समाजसेवी आधिकारिक कर्मचारी भी उपस्थित रहे। उनके निधन पर लोगों ने शोक व्यक्त कियाहै

दलित छात्रा के साथ किडनेप कर के रेप

यह दलित छात्रा के साथ कुछ दिन पहले किडनेप कर के रेप किया रिपोर्ट नहीं लिखी गई जहां जगतगुरु रामभद्राचार्य के क्षेत्र में घटना घटित हुआ लड़की कार्यवाही ना होने से दुखी हो कर आत्महत्या कर लिया उसके बाद रेप हत्या का मुकदमा लिखा गया.

ऐसी घटना रोज हजारों देश में हो रहा है प्रतिदिन नामजद रिपोर्ट लगभग दस हजार हो रहा है NCRB का रिपोर्ट है कुछ उजागर हो जाता है तो रिपोर्ट हो जाता है लेकिन हजारो तो लोक लाज के डर से रिपोर्ट भी नहीं करता है ऐसा क्यों हो रहा है लोग कहते हैं बाबा साहब डा अंबेडकर का संविधान से देश चल रहा है? ऐसा हो रहा है क्यागलती हुआ है संविधान लिखने वाले डा अंबेडकर सेसर साइमन कमिशन रिपोर्ट Cmmunal Award दोहरे मताधिकार अधिनियम में संशोधन करने सेएक संशोधन से 90 प्रतिशत देश के असली मालिकों का जीवन नर्क बन गया है आजाद रहते हुए गुलाम नागरिक हैंआज देश के संविधान में 130 वीं संशोधन हो चुका है देश की कितने आमजनों को मालूम है की 130 वीं संशोधन में क्या लिखा हुआ थाअगर वही सभी 130 नियमों को लागू कर दिया होता तो आज देश में अन्याय अत्याचार नहीं होता देश विश्व के नंबर 1 देश बना हुआ होता लेकिन मनुवादी लोग अपने हिसाब से नियमों को बदला है जिससे देश के 90 प्रतिशत मालिकों को रोटी कपड़ा मकान में उलझा कर रखा है गुलाम को जीने के लिए रोटी चाहिए 82 करोड़ लोगों को 5 किलो की ओकात पर ला कर खड़ा कर दिया है 90 प्रतिशत असली मालिकों के सामने में उनके बहु बेटियों को उठा कर ले जाया जा रहा है उनको नोचा जाता है गूंगा बहरा हो कर रह जाता है संविधान रहते हुए 47 से अभी तक लगभग 7 करोड़ लोगों की हत्या हो चुकी है FIR का रिपोर्ट दर्ज बोल रहा है 10 रेप की करोड़ की रिपोर्ट दर्ज है 13 करोड़ तो विचाराधीन मुकदमा दर्ज अदालत में धूल खा रहा है क्यों 4 करोड़ दलित पिछड़ों अल्पसंख्यकों आदिवासी जेल में हैंअगर बाबा साहब पूना पेक्ट पूना संशोधन नहीं किए होते तो आज देश आविष्कार की जननी होती जापान चीन आज नए नए प्रयोग करके आविष्कार कर रहा है भारत विदेशों के टेक्नोलॉजी के आविष्कार के ऊपर निर्भर है 5फाइटर विमान रफेल सिंदूर आपरेशन में पाकिस्तान ने मार गिराए लेकिन भारतीय एयर जेनरल को मालूम ही नहीं था क्योंकि उसका चिप्स GPS कंट्रोलर फ्रांस में था फ्रांस ने बताया CDS अनिल चौहान को तो उसने सिंगा पुर में जा कर प्रेस कांफ्रेंस में कबूल किया थादोहरे वोट का मताधिकार अधिनियम का संशोधन अगर डा अंबेडकर जी नहीं किए होते तो आज देश में तथागत महामानव गौतम बुद्ध के विचारधारा पर चलते हुए विश्व का नंबर 1 देश होताडा अंबेडकर के द्वारा Communal Award का एक संशोधन ने देश के 90 प्रतिशत असली मालिकों को एक झटके में जीवन नर्क बना दिया है तो समझो संविधान का 130 संशोधन से आज क्या हो गया है किसका क्षति हुआ है यह समीक्षा और विश्लेषण प्रस्तुत है जय निषादराज साहब आनन्द निषाद जी का विचारधारा है सत्य की कसौटी पर परखो जानो छानो बाद में सत्य है तो मानो नमो बुद्धाय

पाकिस्तान-अफ़ग़ानिस्तान संघर्ष के मायने ?

दक्षिण एशिया के इन दो पड़ोसी देशों के रिश्ते हमेशा से जटिल रहे हैं। दोनों देशों के बीच के विवाद की जड़ अंग्रेज़ो के शासन काल में है। अंग्रेज़ों के समय में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ उस वक़्त पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान के बीच भी कुछ इलाकों का बंटवारा हुआ।

-ब्यूरो डेस्क

दक्षिण एशिया के इन दो पड़ोसी देशों के रिश्ते हमेशा से जटिल रहे हौं दोनों देशों के बीच के विवाद की जड़ अंग्रेज़ो के शासन काल में हौ अंग्रेज़ों के समय में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ उस वक़्त पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान के बीच भी कुछ इलाकों का बंटवारा हुआ। पिछले कई दिनों से पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान के बीच लगातार सैन्य संघर्ष जारी हौ पाकिस्तान में अलग-अलग जगहों पर हो रहे आतंकी हमलों के लिए अफ़ग़ानिस्तान की तालिबान सरकार को ज़िम्मदोर ठहराते हुए पाकिस्तान ने अफ़ग़ानिस्तान पर हवाई हमले शुरू किए। पाकिस्तान का अफ़ग़ानिस्तान पर यह आरोप है की अफ़ग़ान तालिबान तहरीक-ए-तालिबान को समर्थन दतेा हौ पाकिस्तान के मेंहु ए कई हमलों में तहरीक-ए-तालिबान के शामिल होने का आरोप इस्लामाबाद की ओर से लगाया जा रहा हौ पाकिस्तान का अफ़ग़ानिस्तान में आतंकी संघटन आय एस आय एस की मजूदगी का भी दावा हौ बीते 3-4 वर्षों से पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान के बीच रूक-रूक कर झड़पें होती रही हौं अक्टूबर 2025 में क़तर की मध्यस्थता से दोनों पड़ोसियों में शांति समझौते का भी प्रयास किया गया। लेकिन इस्लामाबाद और काबुल किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंचो।

कुछ महीनों के विराम के बाद 11 फरवरी से फिर दोनों देशों में जंग छिड़ गई हौ अभी भी दोनों तरफ़ से एक दुसरे की सीमा के अंदर हवाई हमले और सैन्य कार्रवाई जारी हौ दक्षिण एशिया के इन दो पड़ोसी देशों के रिश्ते हमेशा से जटिल रहे हौं दोनों देशों के बीच के विवाद की जड़ अंग्रेज़ो के शासन काल में हौ अंग्रेज़ों के समय में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ उस वक़्त पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान के बीच भी कुछ इलाकों का

बंटवारा हुआ। अंग्रेज़ शासकों ने पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान के बीच एक सीमा रेखा खिंच दी जिसे डुरंड लाईन कहा जाता है। इस डुरंड लाईन से पख़्तून बहुल इलाका पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान में बंट गया। अफ़ग़ानिस्तान ने इस सीमा रेखा को कभी स्वीकार नहीं किया और पाकिस्तान के हिस्से में गए इलाके (खैबर-पख़्तूनख़्वा) पर भी हमेशा दावा किया है। सीमा विवाद पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान के बीच के संघर्ष की एक महत्त्वपूर्ण वजह रही है।

सीमा विवाद और आतंकवाद- इन दो मुद्दों से पाकिस्तान-अफ़ग़ानिस्तान का संघर्ष केवल द्विपक्षीय मामला लग सकता है। लेकिन इस जंग के मायने और परिणाम सिर्फ़ दो देशों तक सीमित नहीं हैं। एक, इस वक़्त दुनिया में अनेक युद्ध चल रहे हैं, जैसे रूस-यूक्रेन युद्ध और इस्राएल-हमास युद्ध। अमेरिका भी ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है। ऐसे में एक और युद्ध से विश्व में अस्थिरता, असुरक्षितता और आर्थिक अनिश्चितता और बढ़ेगी।

दूसरा, हाल के समय में पाकिस्तान और अमेरिका के बीच बढ़ती नज़दीकियों को देखकर इससे इनकार नहीं किया जा सकता की अमेरिका इस जंग के ज़रिये अपना हित साधने की कोशिश करे। अगर अमेरिका मध्यस्थता करके दोनों देशों में शांति प्रस्थापित करता है तो अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प इसे ख़ुद की कामयाबी बता सकते हैंऔर अपने आप को नोबेल शांति पुरस्कार मिलने योग्य बता सकते हैं।

तीसरा, अमेरिका यह भी चाहगेा की रूस किसी तरह अफ़ग़ानिस्तान की मदद करे। अगर ऐसा होता

है तो संभव है रूस का ध्यान यूक्रेन से भटके। इससे यूरोप ऊपर लगातार मंडरा रहा जंग का ख़तरा कुछ हद तक कम होगा। अमेरिका की कोशिशों से अगर यह हो पाता है, तो अमेरिका के यूरोपीय देशों से रिश्ते सुधर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प के दुसरे कार्यकाल में अमेरिका और यूरोप के रिश्तों में क़ाफी कड़वाहट पैदा हुई है।

चौथा, अगर रूस अफ़ग़ानिस्तान की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मदद नहीं करता, और अमेरिका इस युद्ध को रोकने मेंकामयाब होता है, तो इससे अमेरिका अफ़ग़ानिस्तान से भी अपनी नज़दीकियां बढ़ाने की कोशिश करेगा। अफ़ग़ानिस्तान में प्राकृतिक संसाधन और खनिजों का बहुत बड़ा भंडार है, जिसका फायदा अमेरिका लेना चाहगेा।

एक, अगर यह युद्ध लंबे समय तक चलता रहा तो इससे दक्षिण एशिया में अस्थिरता बढ़ेगी और पूरे प्रांत की सुरक्षा को ख़तरा पैदा हो सकता है। दक्षिण, पश्चिम और मध्य एशिया से भारत के कई आर्थिक और रणनीतिक हित जुड़े हुए हैं जिनपर यह युद्ध असर डाल सकता है।

सबसे पहले तो अफ़ग़ानिस्तान भारत के लिए मध्य एशिया में पहुंचने का एक महत्त्वपूर्ण ज़रिया हैं। भारत इस वक़्त चाबहार बंदरगाह और अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा इन दो प्रकल्पों पर काम कर रहा है जो भारत को ईरान और अफ़ग़ानिस्तान के ज़रिये मध्य एशिया से जोड़ते हैं। इन गलियारों का व्यापर और सामान की आवाजाही के लिए परिक्षण भी हो चूका है। पाकिस्तान-अफ़ग़ानिस्तान के बीच अगर लंबी जंग चलती है तो इसका असर भारत के मध्य एशियाई देशों के साथ व्यापार पर होगा।

दूसरा, कूटनीति के मामले में अफ़ग़ानिस्तान फिलहाल दुनिया के कई देशों के लिए एक जटिल समस्या है। इस वक़्त अफ़ग़ानिस्तान के साथ बहुत काम देशों के कूटनीतिक रिश्ते हैं। भारत ने भी अफ़ग़ानिस्तान के तालिबान शासन को मान्यता नहीं दी है। लेकिन भारत ने अफ़ग़ानिस्तान से अपने रिश्ते कायम रखे हैं। संतुलित कूटनीति द्वारा भारत ने इस क्षेत्र में अपने हित संभाले हैं। पाकिस्तान-अफ़ग़ानिस्तान का संघर्ष और इसमें दुसरे देशों का दख़ल देने से शायद भारत को अपने मध्य एशिया नीति पर पुनर्विचार करना पेड़ सकता है।

पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान के बीच का संघर्ष सिर्फ दक्षिण एशिया के लिए ही नहीं बल्कि पूरे एशिया और दुनिया के लिए भी चिंता का विषय है। इस संघर्ष का जारी रहना विश्व की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को असंतुलित कर सकता है ■

सादगी भरी शादियाँ

अमीर लोगों को समाज के लिए उदाहरण क्यों बनना चाहिए

> "आजकल कई शादियाँ इतनी भव्य और महंगी हो गई हैं कि उनमें करोड़ों रुपये तक खर्च किए जाते हैं। बड़े-बड़े होटल, महंगे कपड़े, विदेशी सजावट, मशहूर कलाकारों के कार्यक्रम और कई दिनों तक चलने वाले समारोह अब आम बात हो गए हैं।

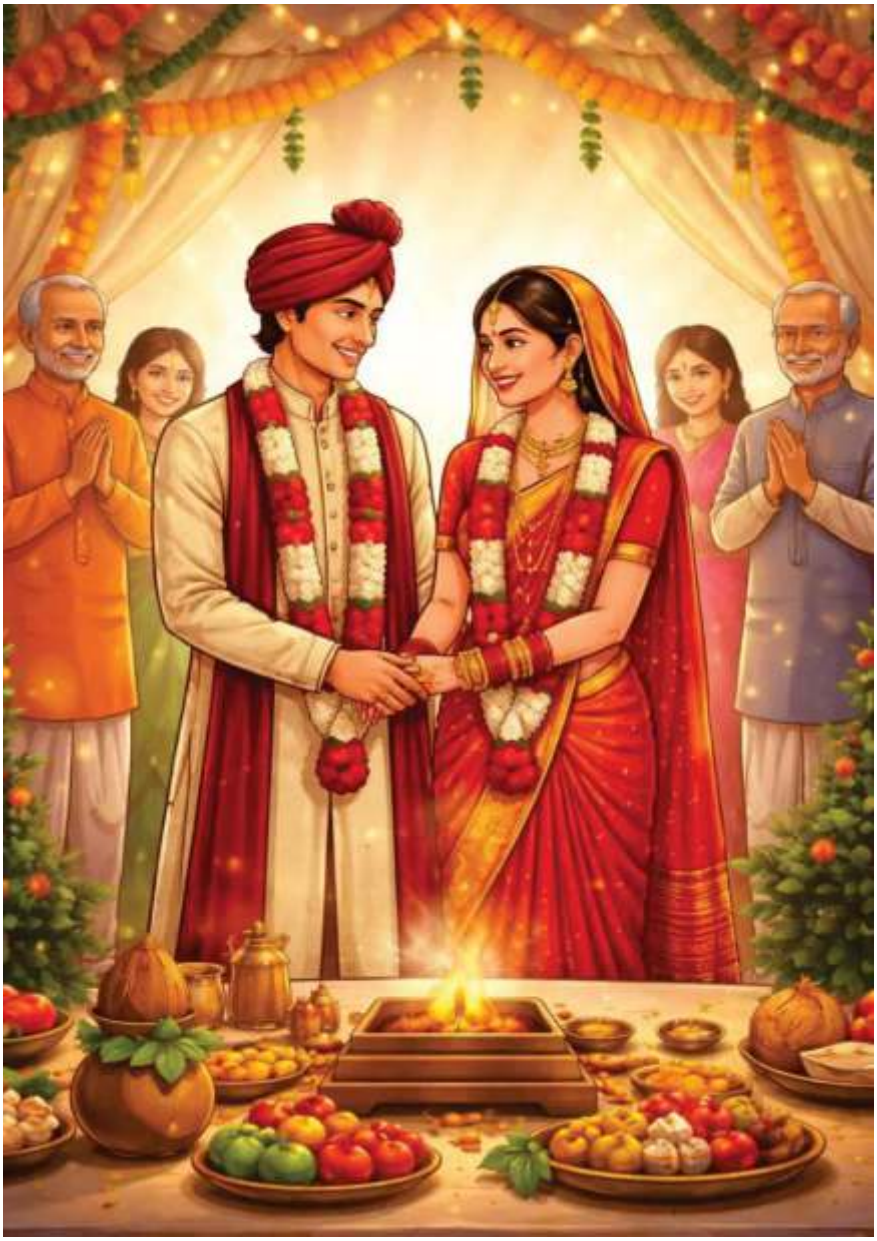

भारत में शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं बल्कि एक बड़ा सामाजिक आयोजन भी माना जाता हौ यहाँ शादी में परिवार, रिश्तेदार, दोस्त और पूरा समाज शामिल होता हौ लेकिन पिछले कुछ वर्षों में शादियों का स्वरूप बहुत बदल गया हौ आजकल कई शादियाँ इतनी भव्य और महंगी हो गई हैं कि उनमें करोड़ों रुपयेतक खर्च किए जाते हैं। बड़े-बड़े होटल, महंगे कपड़े, विदेशी सजावट, मशहूर कलाकारों के कार्यक्रम और कई दिनों तक चलने वाले समारोह अब आम बात हो गए हौं

ऐसी शादियों का सबसे बड़ा प्रभाव समाज के मध्यम और गरीब वर्ग पर पड़ता हौ जब समाज में अमीर लोग बहुत महंगी शादियाँ करते हैंतो बाकी लोगों पर भी वैसी ही शादी करने का दबाव बनने लगता हौ कई परिवार अपनी आर्थिक क्षमता से अधिक खर्च करने लगते हैं।कई बार तो लोग कर्ज लेकर शादी करते हैं ताकि समाज में उनकी प्रतिष्ठा बनी रहो यही कारण हौ कि आज शादी कई परिवारों के लिए खुशी के साथ-साथ आर्थिक बोझ भी बन जाती हौ

ऐसे समय में समाज के बड़े और संपन्न लोगों की जिम्मदेरी और भी बढ़ जाती हौ अगर जिन लोगों के पास बहुत पैसा हौ वे सादगी से शादी करें, तो यह पूरे समाज के लिए एक अच्छा उदाहरण बन सकता हौ इससे यह संदेश जाएगा कि शादी की खुशी दिखावे या खर्च से नहीं बल्कि रिश्तों और संस्कारों से होती हौ

इतिहास में हमें ऐसे कई उदाहरण मिलते हैंजहाँ बड़े

और सम्मानित लोगों ने सादगी को महत्व दिया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की शादी इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। उन्होंने दहेज लेने से साफ मना कर दिया था और केवल एक चरखा और कुछ कपड़े ही स्वीकार किए थे। उस समय भी समाज में दहेज और खर्च की परंपरा थी, लेकिन उन्होंने सादगी और सिद्धांतों को प्राथमिकता दी।

इसी तरह प्रसिद्ध उद्योगपति नारायण मूर्ति और समाजसेवी लेखिका सुधा मूर्ति की शादी भी बहुत साधारण तरीके से हुई थी। उस समय उनके पास बहुत अधिक पैसा नहीं था, लेकिन बाद में जब वे बहुत सफल और संपन्न बने तब भी उन्होंने हमेशा सादगी और जिम्मेदारी का संदेश दिया। सुधा मूर्ति अक्सर कहती हैं कि शादी में फिजूल खर्च करने के बजाय पैसा शिक्षा और समाज सेवा में लगाया जाना चाहिए।

इसके विपरीत आधुनिक समय में कुछ शादियाँ इतनी भव्य हो गई हैं कि वे एक तरह से प्रदर्शन का माध्यम बन जाती हैं। उदाहरण के लिए अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी। इसी तरह ईशा अंबानी और आनंद पीरामल की शादी भी बहुत बड़े स्तर पर आयोजित की गई थी। इन शादियों में कई बड़े उद्योगपति, अंतरराष्ट्रीय कलाकार और फिल्म सितारे शामिल हुए।

हालाँकि यह भी सच है कि जिन लोगों के पास पैसा है, वे अपनी खुशी के लिए खर्च करने का अधिकार रखते हैं। बड़ी शादियों से होटल उद्योग, सजावट, कैटरिंग, संगीत, फोटोग्राफी और कई अन्य क्षेत्रों में

> “मीडिया और सोशल मीडिया का भी इस विषय में बड़ा प्रभाव है। आजकल शादी की तस्वीरें और वीडियो इंटरनेट पर बहुत तेजी से फैलते हैं। जब लोग भव्य और महंगी शादियाँ देखते हैं तो उनके मन में भी वैसी ही शादी करने की इच्छा पैदा होती है। इसलिए जरूरी है कि सादगी भरी शादियों को भी उतना ही महत्व दिया जाए और उन्हें समाज में प्रेरणा के रूप में प्रस्तुत किया जाए।

हजारों लोगों को रोजगार भी मिलता है इसलिए पूरी तरह से बड़ी शादियों की आलोचना करना भी उचित नहीं है।

फिर भी समाज के हित को ध्यान में रखते हुए यह अपेक्षा की जाती है कि बड़े और प्रभावशाली लोग संतुलन बनाए रखें। अगर वे सादगी और जिम्मेदारी का उदाहरण प्रस्तुत करेंगे तो समाज में सकारात्मक बदलाव आ सकता है। जब लोग देखेंगे कि अमीर परिवार भी साधारण तरीके से शादी कर रहे हैं, तो मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग पर अनावश्यक खर्च करने का दबाव कम हो जाएगा।

आज भारत में कई युवा भी इस विषय पर नए विचार अपना रहे हैं। वे सादगी से शादी करने को प्राथमिकता दे रहे हैं। कुछ लोग मंदिर में विवाह करते हैं, कुछ लोग कोर्ट मैरिज करते हैं और उसके बाद परिवार के साथ छोटा सा कार्यक्रम रखते हैं। इससे खर्च कम होता है और शादी का मूल उद्देश्य भी बना रहता है।

साधारण शादी के कई फायदे भी हैं। सबसे पहला फायदा यह है कि परिवार को आर्थिक बोझ नहीं उठाना पड़ता। कई बार शादी के खर्च के कारण परिवार वर्षों तक कर्ज में डूबे रहते हैं। अगर शादी सादगी से हो तो यह समस्या कम हो सकती है। दूसरा फायदा यह है कि पैसा बचाकर उसे किसी उपयोगी काम में लगाया जा सकता है, जैसे बच्चों की शिक्षा, घर की जरूरतें या समाज सेवा।

इसके अलावा सादगी से शादी करने से सामाजिक समानता का संदेश भी जाता है। समाज में अमीर और गरीब के बीच जो दिखावे की खाई बढ़ रही है, उसे कम करने में भी यह मददगार हो सकता है।

मीडिया और सोशल मीडिया का भी इस विषय में बड़ा प्रभाव है। आजकल शादी की तस्वीरें और वीडियो इंटरनेट पर बहुत तेजी से फैलते हैं। जब लोग भव्य और महंगी शादियाँ देखते हैं तो उनके मन में भी वैसी ही शादी करने की इच्छा पैदा होती है। इसलिए जरूरी है कि सादगी भरी शादियों को भी उतना ही महत्व दिया जाए और उन्हें समाज में प्रेरणा के रूप में प्रस्तुत किया जाए।

सरकार और सामाजिक संस्थाएँ भी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। कई जगहों पर सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जहाँ कम खर्च में कई जोड़ों की शादी करवाई जाती है। इससे गरीब परिवारों को बहुत राहत मिलती है और समाज में सादगी का संदेश भी फैलता है।

अंत में यह समझना जरूरी है कि शादी का असली अर्थ दिखावा नहीं बल्कि दो लोगों का साथ और दो परिवारों का मिलन है। खुशियाँ महंगे कपड़ों, बड़ी सजावट या भव्य कार्यक्रमों से नहीं बल्कि प्यार, विश्वास और संस्कारों से बनती हैं।

इसलिए यदि समाज के बड़े और संपन्न लोग सादगी से शादी करके उदाहरण प्रस्तुत करें, तो यह पूरे समाज के लिए प्रेरणा बन सकता है। इससे न केवल अनावश्यक खर्च कम होगा बल्कि समाज में संतुलन, जिम्मेदारी और सादगी की भावना भी मजबूत होगी। वास्तव में एक अच्छी शादी वही है जिसमें खुशी हो, सम्मान हो और परिवारों का स्नेह हो। अगर यह सब सादगी के साथ हो जाए, तो वही सबसे बड़ा उत्सव बन जाता है। ■

योगी आदित्यनाथ की विदेश यात्रा से विकास और हिंदुत्व मॉडल हुआ मजबूत !

-शुभम यादव

राजनीतिक विश्लेषक बताते हैंकि मुख्यमंत्री योगी का यह दौरा 2027 विधानसभा चुनावों में योगी सरकार की छवि को चमकाने का साधन बनेगा। तभी तो उनका यह दौरा आगामी चुनावों से पहले योगी सरकार की विकास-केंद्रित छवि को रेखांकित करता है। वहीं विपक्ष के सवालों के बावजूद निवेश कूटनीति को बढ़ावा देता है।

उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री और फायरब्रांड हिन्दू नेता योगी आदित्यनाथ की हालिया सिंगापुर-जापान यात्रा प्रदेश की आर्थिक महत्वाकांक्षाओं को मजबूत करने का एक सशक्त प्रयास है। भले ही सीएम का यह दौरा निवेश आकर्षण और औद्योगिक साझेदारी पर केंद्रित रहा। लेकिन इन दौरों से इस बात के स्पष्ट संकेत मिले कि विकास और हिंदुत्व के मॉडल पर गतिशील यूपी सरकार के लिए निकट भविष्य में 1 ट्रिलियन डॉलर की सूबाई इकॉनमी वाले लक्ष्य को पाना बिल्कुल कठिन नहीं है।

आर्थिक विश्लेषक बता रहे हैंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सहयोगी उपमुख्यमंत्री और भरोसेमंद मंत्रियों के साथ 22 से 26 फरवरी 2026 तक चार दिवसीय विदेश यात्रा पर रहे, उसका अपना महत्व है। सर्वप्रथम उन्होंने 23-24 फरवरी को सिंगापुर की यात्रा की और फिर 25-26 फरवरी को जापान की यात्रा किए।इन दोनों यात्राओं से उन्हें अभूतपूर्व अनुभव हासिल हुआ, जिसके कुछ पलों को उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा भी किया था। कहना न होगा कि 2017 में यूपी की कमान थामने के बाद उनका यह पहला

आधिकारिक विदेश दौरा था, जहां उन्होंने निवेशकों, उद्योग प्रतिनिधियों और प्रवासी भारतीयों से मुलाकात की।

इसलिए योगी की इस विदेश यात्रा के अपने सूबाई मायने हैं,जिसे समझने की जरूरत हौ पहला, यह यात्रा यूपी को 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को गति दगेी, विशषेकर अवसंरचना, लॉजिस्टिक्स, डेटा सेंटर और कौशल विकास में निवे श पर फोकस के साथ। दूसरा, सिंगापुर-जापान जैसे औद्योगिक केंद्रों से साझदेारी प्रदेश को 'मेक इन यूपी' हब बनाने में मदद करेगी, जो राज्य की वैश्विक ब्रांडिंग को मजबूत करेगी। तीसरा, योगी आदित्यनाथ की सिंगापुर-जापान यात्रा से उत्तर प्रदेश को कुल 2.5 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 1.5 लाख करोड़ रुपये के एमओयू (समझौता ज्ञापन) पर हस्ताक्षर हो चुके हैं।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, सिंगापुर से लगभग 1 लाख करोड़ रुपये केनिवे श प्रस्ताव मिले हैं,जिनमें 60 हजार करोड़ के एमओयू शामिल हौं वहीं, जापान से अतिरिक्त निवेश प्रतिबद्धताएं आई हैं, जो कुल को 2.5 लाख करोड़ तक ले गई। इन निवेश प्रस्तावों में सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, ऑटोमोटिव, कृषि मशीनरी, लॉजिस्टिक्स, ग्रीन हाइड्रोजन और एविएशन (एमआरओ) जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित हौ वो भी नामचीन कंपनियों, जैसे- कुबोटा, स्पार्क मिंडा, सुजुकी, होंडा और मित्सुई यदि से, जिनकी अपनी

वैश्विक कारोबारी साख हौ

जानकारों के मुताबिक, यदि सरकार इन प्रस्तावों को तय समयसीमा में धरातल पर उतारने का लक्ष्य रखती है, और अपने मकसद में कामयाब होती है तो उत्तरप्रदेश मेंलाखों रोजगार सृजित होंगे और सूबे के1 ट्रिलियन डॉलर अर्थ व्यवस्था के लक्ष्य को महत्वपूर्ण गति मिलेगी। खास बात यह कि योगी आदित्यनाथ की सिंगापुर-जापान यात्रा ने भाजपा को विकास और हिंदुत्व के मॉडल को मजबूत करने का मौका दिया हौ

राजनीतिक विश्लेषक बताते हैंकि मुख्यमंत्री का यह दौरा 2027 विधानसभा चुनावों में योगी सरकार की छवि को चमकाने का साधन बनेगा। तभी तो उनका यह दौरा आगामी चुनावों से पहले योगी सरकार की विकास-केंद्रित छवि को रेखांकित करता हौ वहीं विपक्ष के सवालों के बावजूद निवेश कूटनीति को बढ़ावा दतेा हौ इससे यूपी की अर्थव्यवस्था को ग्लोबल पटल पर मजबूती मिलेगी। यात्रा से प्राप्त 2.5 लाख करोड़ निवेश प्रस्तावों को भाजपा 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य से जोड़कर प्रचारित करेगी, जो युवाओं में रोजगार सृजन का वादा मजबूत करेगा।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि प्रवासी भारतीयों के साथ संवाद ने योगी की वैश्विक अपील बढ़ाई, जो 2027 चुनावों मेंवोटबैं क को एकजुट करने में सहायक होगा। सच कहा जाए तो योगी का यह दौरा यूपी को ग्लोबल इकोनॉमी में स्थापित करेगा, जो केंद्र में भाजपा की नीतियों को समर्थन दगेा। वहीं, हिंदुत्व एंगल (जैसे जापान मंदिर दर्शन) ने सांस्कृतिक डिप्लोमेसी को जोड़ा है, जो पार्टी की वैचारिक मजबूती बढ़ाएगा।

यह बात दीगर है कि सूबे की मुख्य विपक्षी पार्टी सपा के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी की इस अभूतपूर्व यात्रा पर तंज कसा, और इसे 'भारत छोड़कर भागना' बताकर विपक्षी हमला बोला। यह उनकी बचकाना सियासी हरकत है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वास्तव में, निवेश सफलता ने विपक्ष के आरोपों को कमजोर किया, और भाजपा को योगी आदित्यनाथ को प्रदेश में 'विकास पुरुष' के रूप में पेश करने का आधार दिया, जिसका अपना राजनीतिक महत्व हौ ■

बांग्लादेश की नई सरकार में

“

बांग्लादेश में नवगठित हुकूमत के साथ करीब एक ड़ेढ़-सालों से दंगों का दंश झेल रहे देश में आखिरकार नई सुबह का आगाज हो चुका है। आवाम को इस दिन का लंबे वक्त से इंतजार था। वहां काफी जद्दोजहद और राजनीतिक अस्थिरता के बीच हुए आम चुनावों में बीएनपी ने बड़े मार्जिन से विजय हासिल की है।

-ब्यूरो डेस्क

पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में तारिक रहमान के रूप में नई सरकार शपथ ले चुकी हौ खास बात ये हैरहमान के नेतृत्व वाली नई सरकार में दो हिंदू सांसदों को मंत्री बनाया गया हौ उनके इस निर्णय को भारत के साथ प्रत्यक्ष रूप से बिगड़े संबंधों को सुधारने की पहल के रूप में समूची दुनिया देख रही हौ इस कदम से चीन-पाकिस्तान चिड़े भी हौं वो नहीं चाहते कि बांग्लादेश भारत या उनसे वास्ता रखने लोगों को तवज्जो दो लेकिन, तारिक रहमान ने उनके नापाक मंसूबों को धता बताते हुए, बड़ी सूझबूझता से कदम आगे बढ़ाया। बीते कुछ महीनों में 11 हिंदुओं के साथ हुई निर्मम बर्बरता ने बांग्लादेश की न सिर्फ थू थू करवाई, बल्कि दशको से मधुर संबंधों को भी पटरी से उतार दिया था। इसको लेकर दोनों मुल्कों में तल्खियां बनी हुई थीं। रहमान जानते हैंअगर माहौल ऐसा ही बरकरार रहा, तो रिश्तो की दूरियां घटने वाली नहीं? ऐसी अखरती दुश्वारियों पर गौर करते हुए ही रहमान ने अपनी कैबिनेट में हिंदू समुदाय से ताल्लुक रखने वाले सांसदों को अहम औहदे सौंपे ताकि रिश्तों में फिर से नरमी लाई जा सके। भारत ने भी उनके निर्णय को सराहा हौ

गौरतलब हैं कि तारिक रहमान के आगाज से पूर्व बांग्ला-हिंदुओं पर किस तरह के अत्याचार हुए हैं और हो भी रहे हैं? ऐसी निदंनीय घटनाओं को तत्काल प्रभाव से रोकने की चुनौती तारिक रहमान के सामने अभी भी खड़ी हौ हालांकि, रोकने के लिए वह अपने कदम तेजी से बढ़ा रहे हौं प्रधानमंत्री रहमान सबसे पहले पूर्व की अंतरिम सरकार के मुखिया रहे मोहम्मद यूनस के अटपटे और संबंध बिच्छेद भरे निर्णयों की समीक्षा करेंगे। उनका झुकाव भारत को परेशान करने वाली पाकिस्तान-चीन की संयुक्त खुराफाती नीतियों की ओर ज्यादा रहा था। रहमान अच्छे से समझते हैंकि जबतक मोहम्मद यूनस कार्यकारी प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने

हिंदू मंत्रियों की आमद

भारत के साथ संबंधों को बिगाड़ने की हर संभव कोशिशें कीं। कुछ उन्होंने की और कुछ दूसरे देशों ने करवाई? दूसरे देश कौन से हैं जिनके नाम लेने की शायद जरूरत नहीं? सभी जानते हैं।

प्रधानमंत्री तारिक रहमान भारतीय हुकूमत का साथ लेकर और अपनी कैबिनेट में अल्पसंख्यक हिंदू मंत्रियों की आमद के साथ बांग्लादेश में अगले पांच सालों तक समानांतर सरकार चलाना चाहते हैं। इसी को ध्यान में रखकर जब उनकी पार्टी बीएनपी चुनावों में जीती तो सबसे पहले वह अपने धुरविरोधी विपक्षी नेता और जमात-ए-इस्लामी प्रमुख शफीकुर रहमान के बिना बुलाए, ढ़लती शाम के बाद उनके आवास पहुंच गए। चुनावी गुस्सेबाजियों के इतर उनसे नई सरकार में सहयोग की गुजारिश करी। विपक्षी नेता ने भी राजनीतिक दुश्मनी छोड़कर उनका गर्मजोशी से अपने घर पर स्वागत किया। दरअसल, इस तरह की खूबसूरत परंपरा का प्रचार-प्रसार पूरे विश्व में होना चाहिए, कि चुनाव बाद विपक्ष से सत्ता पक्ष को कैसे व्यवहार करना चाहिए। ये उन देशों के लिए सीख भी है जहां पक्ष-विपक्ष आपस में अनैतिक कुकर्मों की सभी सीमाएं लांघ रहे हों। रहमान उस विपक्षी नेता के घर भी पहुंचे जिनकी पार्टी चुनावों में तीसरे स्थान पर रही। नेशनल सिटीजन पार्टी के नाहिद इस्लाम को भी गले लगाया और बांग्लादेश के विकास में उनसे भी सहयोग मांगा। राजनीति में ऐसी तस्वीरों का दिखना दुर्लभ होता है, लेकिन बांग्लादेश में दिखी।

रहमान की जीत पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का उन्हें भाई बताना और उनकी जीत की खुशी में फूल-मिठाईयां को ढाका भेजना भी धूमिल संबंधों में रस भरने जैसा कहा जाएगा। साथ ही रहमान के शपथ में भारत सरकार की ओर से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का पहुंचना भी सुखद और नए संबंधों में नए सिरे से गढ़ने जैसा है। नए रंग में रिश्तों को रंगने की दरकार इसलिए भी महसूस होने लगी है क्योंकि बांग्लादेश की सत्यानाशी के लिए जिस तरह से चीन-पाकिस्तान मिलकर घेराबंदी कर रहे हैं जिसका अंदाजा नवगठित सरकार के मुखिया को भी है। बांग्ला-हिंदू संबंध जितने बिगड़ेंगे, उतना फायदा ये दोनों मुल्क मिलकर उठाएंगे। पूर्व की कार्यकारी सरकार को इन्होंने कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया। पाकिस्तान के सह पर बांगाली और हिंदुओं को खूब लड़ाया गया। लेकिन संपन्न हुए 13वें राष्ट्रीय चुनाव में तीन हिंदू समुदाय के सांसद जीते हैं जिनमें निताई रॉय चैधरी को स्पीकर, चंटगांव से जीते अधिवक्ता दीपेन दीवान को पहाड़ी क्षेत्रों के संरक्षण के लिए मंत्री, तो वहीं गोयेश्वर रॉय चैधरी को महत्पूर्ण रेलमंत्री बनाया गया है।

बांग्लादेश में नवगठित हुकूमत के साथ करीब एक डेढ़-सालों से दंगों का दंश झेल रहे देश में आखिरकार नई सुबह का आगाज हो चुका है। आवाम को इस दिन का लंबे वक्त से इंतजार था। वहां काफी जद्दोजहद और राजनीतिक अस्थिरता के बीच हुए आम चुनावों में बीएनपी ने बड़े मार्जिन से विजय हासिल की है। कुल संसदीय 298 सीटों में 297 पर चुनाव हुए, उनमें से रिकॉर्ड 209 सीटें बीएनपी ने जीतीं। दूसरे नंबर पर जमात-ए-इस्लामी पार्टी रही जिसने 68 सीटें जीतीं। तारिक रहमान की नई कैबिनेट में डॉ. खलीलुर रहमान को विदेश मंत्री, सलाहुद्दीन अहमद को गृह मंत्री, डॉ. अमीर खसरू महमूद को वित्त एवं प्लानिंग की जिम्मदेारी सौंपी गई है। कुल मिलाकर तारिक रहमान ने शिक्षित और बुद्धिजीवी लोगों से अपनी कैबिनेट को सजाया हैं। कैबिनेट में कुल 50 मंत्री हैं जिनमें 25 कैबिनेट और 24 राज्य मंत्री शामिल हैं ■

रणनीतिक संपदा बनता सोना

-ब्यूरो डेस्क

सोना अब सिर्फ कीमती धातु नहीं रहा, बल्कि गैरसरकारी मुद्रा के रूप में भी इसे पहचाना जाता है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसका मूल्य 5,170 डॉलर प्रति औंस (31.103 ग्राम) तक पहुंच चुका है, जबकि घरेलू बाजार में यह प्रति 10 ग्राम 1.61 लाख रुपये से ऊपर है. सितंबर, 2024 से इसमें कोई बड़ी या स्थायी गिरावट नहीं देखी गयी है. ऐसे में,सोने केदाम लगातार बढ़ने को सिर्फ तेजी नहीं कह सकते, यह वैश्विक वित्तीय प्रणालियों में संरचनात्मक बदलाव का संकेत है. सोने में स्थायी तेजी का मुख्य कारण दरअसल इसमें तेजी से बढ़ता निवेश है और पारंपरिक निवेशक भी इसमें निवेश कर रहे हैं. यही नहीं, अब सोने की कीमत हर उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद लगभग आठ से नौ महीनों तक स्थिर रहती है.

गौर करने की बात यह भी है कि खासकर पिछले दो वर्षों में सोने मेंनिवे श करना पहले की तुलना में

> “ब्याज दरें ऊंची होने केबावजू द सोने में तेजी आना एक बड़े बदलाव का सूचक है. पश्चिम एशिया का संकट गहराने से रुपये में गिरावट आने और महंगाई बढ़ने से सोने केदाम में और तेजी आने की आशंका बढ़ गयी है.

कहीं अधिक आकर्षक हो गया है. सितंबर, 2024 में पहली बार सोना 75,000 रुपये से ऊपर चला गया था. उसके बाद मामूली गिरावट के बावजूद इसकी कीमत में लगातार वृद्धि ही होती रही है. विगत 29 जनवरी को यह 1.75 लाख रुपये से ऊपर पहुंच गया था और अभी इसकी कीमत करीब 1.6 लाख रुपये है. ऐसे में,सोने के 1.30 लाख रुपये से नीचे गिरने की संभावना कम है.

सोने की कीमत पांच साल में 40,000 से 75,000 रुपये तक पहुंच गयी, जबकि एक लाख से डेढ़ लाख का सफर इसने करीब छह महीने में तय कर लिया. उनतीस अगस्त, 2019 को सोना पहली बार 40,220 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया था. फिर 25 सितंबर, 2024 को यह पहली बार 75,248 रुपये हो गया. तेईस जुलाई, 2025 को सोना पहली बार एक लाख रुपये केपार गया, जबकि 21 जनवरी, 2026 को यह डेढ़ लाख रुपये का स्तर पार कर गया.

परंपरागत रूप से जब ब्याज दरें बढ़ती हैं, तब सोने की कीमत घटती है, क्योंकि सोने में निवेश पर ब्याज नहीं मिलता. वर्ष 2023 से 2025 के बीच इस परिदृश्य में बदलाव आया है. ब्याज दरें ऊंची होने केबावजूद सोने की कीमत बढ़ रही है, जो एक बड़े परिवर्तन का संकेत है. अब निवेशक सरकारी बॉन्ड पर कम भरोसा कर रहे हैं और सोने को एक गैर-सरकारी मुद्रा के रूप में देख रहे हैं. सरकार द्वारा इसका मूल्यवर्धन नहीं किया जा

सकता, क्योंकि इसकी कीमत बाजार की स्थिति, भू-राजनीतिक हालात, अर्थव्यवस्था की स्थिति आदि पर निर्भर करती है. अभी रुपया कमजोर होने केकारण सोना अधिक आकर्षक हो गया है, जिससे गोल्ड इटीएफ में निवेश में तेजी आयी है.

लंबी अवधि के लिए सोना न केवल जोखिम से सुरक्षा का साधन है, बल्कि एक रणनीतिक संपदा भी बन चुका है. पश्चिम एशिया, एशिया और पश्चिमी यूरोप में अस्थिरता के कारण निवेशकों का डॉलर आधारित प्रणाली में विश्वास घट रहा है. इसके मुकाबले, विश्व के केंद्रीय बैं क पिछले चार वर्षों से लगभग 1,000 टन सोना खरीद रहे हैं, ताकि डॉलर पर निर्भरता कम हो सके. वहीं सोने की आपूर्ति मेंभी कमी देख ने को मिली है, क्योंकि हाल के वर्षों में कोई नयी खदान शुरू नहीं हुई है,इसके अलावा खदानों को संचालित करने मेंभी समय लगता है. पश्चिम एशिया का संकट गहराने से रुपये मेंगिरावट आने और महंगाई बढ़ने से सोने के दाम में और ते जी आने की आशंका बढ़ गयी है.

इधर, सेबी ने एक्टिव इक्विटी स्कीम को सोना और चांदी में निवेश की अनुमति दी है. इसका उद्देश्य यह है कि जब शेयर बाजार में गिरावट आये, तब सोने और चांदी की संभावित बढ़त से नुकसान की पूर्ति हो सके. सेबी का यह निर्णय सोना-चांदी के लिए लाभदायक साबित होगा. जाहिर है, इससे सोना-चांदी की मांग और कीमत, दोनों में इजाफा होगा. हालांकि इस साल सोने की कीमत में करीब 20 फीसदी और चांदी की कीमत में 14 प्रतिशत की वृद्धि पहलेही हो चुकी है.

सोने की कीमत बढ़ने के साथ इसमें निवे श की मांग भी बढ़ी है और आज के युवा भी इसमें

अग्रणी हैं. आंकड़ों के अनुसार, करीब 65 प्रतिशत मिलेनियल्स, यानी युवा सोने के बजाय डिजिटल गोल्ड, इटीएफ और म्यूचुअल फंड में निवेश करना पसंद कर रहे हैं. वर्ष 2025 मेंगोल्ड इटीएफ में निवेशकों की भागीदारी में 60 फीसदी की वार्षिक वृद्धि देखी गयी, जो दर्शाती है कि आम लोग अब पारंपरिक गहनों से हटकर वित्तीय सोने मेंरुचि ले रहे हैं. निवेशकों में से 85 फीसदी से अधिक सोने को धन के संरक्षण और महंगाई से सुरक्षा का माध्यम मानते हैं.

शहरी क्षेत्र में डिजिटल सोने की लोकप्रियता बढ़ रही है, हालांकि ग्रामीण क्षेत्र में अब भी लोग सोना खरीदना या सोने केबदले कर्ज लेना पसंद करते हैं. इस तरह, बदलते आर्थिक परिदृश्य में सोने मेंनिवे श एक बहुत ही लोकप्रिय और सुरक्षित विकल्प बना हुआ है. वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल और अन्य वित्तीय सर्वेक्षण बताते हैंकि भारतीयों में सोने मेंनिवे श के रूप में रुचि बढ़ी है. सोना अभी तक सीधे लेनदने के लिए आधिकारिक मुद्रा नहीं है, लेकिन लोग इसे गैर-सरकारी मुद्रा के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं. ■

प्रबंधन कौशल में नाकाम साबित हो रही है कांग्रेस

असम में चुनाव होने वाले हैं और वहां कांग्रेस कठिन चुनाव में फंसी हुई है . इसी कारण उसने वहां चुनाव की कमान अघोषित तौर पर प्रियंका गांधी वाड्रा को सौंप रखी है. उन्हें स्क्रीनिंग कमेटी, यानी टिकटों की वितरण समिति का प्रमुख, डीके शिवकुमार तथा भूपेश बघेल को पर्यवेक्षक और भंवर जितेंद्र सिंह को प्रभारी बनाया गया है.

-ब्यूरो डेस्क

वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से कांग्रेस में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा. पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत से वंचित करने से कांग्रेस को जो बढ़त मिली थी, उसे उसने अपनी नादानियों से गंवा दिया है. पार्टी के बागी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने में टालमटोल और मीडिया के साथ सामंजस्य न बनाना इसकी बड़ी वजहें हैं. असम में चुनाव होने वाले हैं और वहां कांग्रेस कठिन चुनाव में फंसी हुई है. इसी कारण उसने वहां चुनाव की कमान अघोषित तौर पर प्रियंका गांधी वाड्रा को सौंप रखी है. उन्हें स्क्रीनिंग कमेटी, यानी टिकटों की वितरण समिति का प्रमुख, डीके शिवकुमार तथा भूपेश बघेल को पर्यवेक्षक और भंवर जितेंद्र सिंह को प्रभारी बनाया गया है. यानी वहां प्रियंका की पूरी टीम जुटी हुई है. ऐसे में, वहां जो भी नतीजे आयेंगे, उसकी जिम्मेदारी प्रियंका के मत्थे आयेगी. अगर कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, तो यही कहा जायेगा कि उत्तर प्रदेश की तरह असम में भी प्रियंका विफल हो गयीं.

भाजपा के लिए असम का चुनाव सिर्फ सत्ता में वापसी तक सीमित नहीं है, उसके फोकस में प्रियंका को विफल साबित करना भी है. इस वजह से भाजपा वहां हरसंभव तरीके आजमा रही है. वह मतदाताओं के बीच यह संदेश भी देना चाहती है कि कांग्रेस में अफरातफरी का माहौल है. इसी के तहत मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा कांग्रेस में सेंधमारी की हरसंभव कोशिशों में जुट गये हैं.यह बात समझ से परे है कि जब कांग्रेस का कोई नेता बागी तेवर दिखाने लगता है या उसके पाटी छोड़कर जाने का स्पष्ट संदेश मिल जाता है, तब भी उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती.

असम में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेन बोरा ने 16 फरवरी को पार्टी से इस्तीफा दे दिया था. पर पार्टी आलाकमान ने इस्तीफा स्वीकार न कर उन्हें मनाने की कोशिश की. खुद राहुल गांधी ने उनसे फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया. पर बोरा के इस्तीफे केअगले ही दिन हिमंता उनके घर पहुंच गये और फिर यह तय हुआ कि बोरा 22 फरवरी को भाजपा में औपचारिक रूप से शामिल होंगे. जब यह निश्चित हो गया था कि बोरा कांग्रेस में टिकने वाले नहीं हैं, तब भी पार्टी ने उन्हें निष्कासित क्यों नहीं किया? कांग्रेस केवल मूकदर्शक बनी रही. अगर उन्हें पहले ही निलंबित या निष्कासित कर दिया जाता, तो लोगों में यह संदेश जाता कि पार्टी ने उन्हें निकाल दिया और इसी कारण भाजपा का दामन थामना उनकी मजबूरी बन गया थी.

वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मणिशंकर अय्यर की बयानबाजी से भी पार्टी नेतृत्व मुसीबत में है. कांग्रेस ने जो गलती बोरा के साथ की, क्या वही मणिशंकर अय्यर को लेकर नहीं कर रही? अय्यर बतौर कांग्रेस नेता बार-बार ऐसे बयान दते रहे हैं, जो भाजपा के लिए कांग्रेस पर हमला करने के हथियार बन जाते हैं. हाल ही में उन्होंने इंडिया गठबंधन के संयोजक पद के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नाम की पैरवी कर कांग्रेस व राहुल गांधी के लिए असहज स्थिति पैदा कर दी. इस पर एआइसीसी के मीडिया विभाग प्रमुख पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अय्यर का पिछले कुछ वर्षों से कांग्रेस से कोई संबंध नहीं है और वह जो कुछ कहते-लिखते हैं, वह उनका निजी विचार है.

मणिशंकर अय्यर ने कोई पहली बार पार्टी लाइन से हटकर बयानबाजी नहीं की है. उनका बार-बार बयान देकर कांग्रेस नेतृत्व को परेशानी में डालना और फिर कांग्रेस प्रवक्ताओं का यह कहना, कि पिछले कुछ वर्षों से कांग्रेस से कोई संबंध नहीं है, भी समझ से परे है.अगर पार्टी का किसी ने ता से कोई संबंध नहीं है, तो फिर उसे या उसके बयानों को ढोने का क्या मतलब है? कांग्रेस नेतृत्व अपने ऐसे नेताओं पर कड़ी कार्रवाई करने का साहस क्यों नहीं कर पाती कि दूसरा कोई नेता इस तरह की बयानबाजी करने से पहले दो बार सोचे? किस बात को पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र के तौर पर बढ़ावा देना है और किसे अनुशासनहीनता मानना है, इसमें कांग्रेस का नेतृत्व अंतर नहीं कर पा रहा है.

कांग्रेस की इस पूरी विफलता की एक वजह मीडिया के साथ उसके सामंजस्य की कमी भी है. चुनाव के समय पार्टियों में भगदड़ मचना स्वाभाविक बात है.पर इससे संदेश यह जाता है कि कांग्रेस के खेमे में निराशा का माहौल है और उसके नेता इधर-उधर भाग रहे हैं. ऐसे में,मीडिया प्रबंधन बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है. राजनीति में नैरेटिव काफी मायने रखता है और इसमें मीडिया की अहम भूमिका होती है. लेकिन कांग्रेस मीडिया के किसी भी माध्यम के जरिये अपनी बात पूरी ताकत के साथ नहीं रख पा रही है.

एआइ इंपैक्ट समिट में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा कमीज उतारकर विरोध करने के मसले को भाजपा ने मीडिया और सोशल मीडिया का सहारा लेकर जिस तरह देश के 'अपमान' के साथ जोड़ दिया, उस पर भी कांग्रेस को विचार करने की जरूरत है. इस मामले मेंभी काग्रे स हाथ पर हाथ धरे बैठे रही. इस घटनाक्रम ने भी दिखाया है कि कांग्रेस का मीडिया मनैजमटें कितना लचर है कि वह अपने जायज लोकतांत्रिक अधिकारों की बात भी सही तरीके से नहीं रख पा रही. ऐसे में,दूसरे ज्वलंत मसलों पर अपने विचार कैसे आगे बढ़ा पायेगी, यह सोचने वाली बात है. ■

एय्याशी के अड्डे की आपबीती

सितंबर 2025 में पीड़ित मरीना लैसरडा अमेरिकी सत्ता के केंद्र कैपिटल हिल पहुंचीं और पहली बार सरेआम जेफरी एपस्टीन के कुकर्मों का सार्वजनिक खुलासा किया।

-ब्यूरो डेस्क

पहली बार सितंबर 2025 में कैपिटल हिल के सामने खड़ी मरीना लैसरडा ने जेफरी एपस्टीन के हाथों अपने यौन शोषण के बारे में सरेआम अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा, ''इतने वर्षों बाद मरे मन से बोझ हट गया है'' 2019 में एपस्टीन के खिलाफ फेडरल जांच में लैसरडा का जिक्र ''नाबालिग पीड़ित 1'' है। उन्हें 2002 में एपस्टीन ने नौकरी पर रखा था, तब वे सिर्फ 14 साल की थीं। एक दोस्त ने उन्हें सुझाव दिया कि वे एक अमीर आदमी को 'मसाज' देकर 300 डॉलर कमा सकती हैं। वे याद करती हैं, ''उसने काम को साफ-सुथरा बताया था।'' वे 13 साल की उम्र से ही काम करने लगी थीं, फैक्ट्री में नौकरी, वे ट्रेस का काम, बैकग्राउंड मॉडलिंग, ऑफिस का काम वगैरह-वगैरह। परिवार का गुजारा चलाना उन्हीं के जिम्मे था। लैसरडा ने बताया, ''14 साल की उम्र में घर का बोझ मुझ पर था। मुझेबस पैसे कमाने थे।''

वे एपस्टीन के मैनहट्टन मशें न पहुंचीं, तो हैरान रह गईं। विशाल लकड़ी का दरवाजा। वेटिंग रूम में नेताओं, राज परिवारों और राष्ट्रपतियों जैसे रसूखदारों की तस्वीरें लगी थीं। छत पर नग्न औरतों के ब्लैक-ऐंड-व्हाइट स्केच वाला हॉलवे था। मसाज रूम में विक्टोरिया सीक्रेट ब्रांड के लोशन थे जिसमें कुछ से वे वाकिफ थीं, कुछ से नहीं।

वे बताती हैं, ''मुझे याद है कि मैं छत की ओर देखरही थी। बड़ा सुंदर और सुखद लग रहा था। मैं कितनी

नासमझ थी!" लैसरडा ने कहा कि उसके बाद जो हुआ, वह उनसे किए गए वादे जैसा बिल्कुल नहीं था। जब हदें बढ़ीं, तो वे जम गईं। उन्होंने सिर हिलाकर मना कर दिया। एपस्टीन मुस्कराया और कहा, "धीरे-धीरे सहज हो जाओगी।" एक दोस्त ने उन्हें "तनाव" न लेने को कहा। वे कहती हैं, "तब मैंने मन में सोचा था, यह आदमी तो हैवान है। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी।" वे 300 डॉलर लेकर लौट आईं। लेकिन घर का खर्च चलाना मुश्किल होता जा रहा था, उनकी मां कोई काम करने के काबिल नहीं थीं, इसलिए दोबारा कॉल आया, तो वे चली गईं।

वे बताती हैं, दूसरी बार उसने पहले कुछ नहीं कहा। बड़ी विनम्रता से पेश आया था। फिर, धीरे-धीरे हदें धुंधली होती गईं। बस हल्के-हल्के, एक-एक कदम। फिर, वे कहती हैं, "इससे पहले कि मुझे पता चलता, मेरा रेप हो रहा था और मुझे पता भी नहीं पता चला कि कैसे होने लगा।"

वर्षों बाद, उन्होंने दूसरी पीड़ितों से बात करनी शुरू की, तो कुछ ऐसा एहसास हुआ जिससे वे हैरान रह गईं। उन्हें याद आया कि, "उन सबने कहा कि उसने उनके साथ रेप किया था।" लेकिन फोन पर एक लड़की चुप हो गई। उन्होंने धीरे से कहा, "तुम क्या बात कर रही हो मरीना, जेफरी एपस्टीन ने हम लोगों के साथ बलात्कार किया?"

बात वहीं अटकी रही। दूसरी ओर से पीड़िता ने चेताया कि वह उन्हें अलग-थलग करके ऐसी स्थिति में ला देगी कि दूसरे दुर्दशा देख डरेंगे। वे हक्का-बक्का थीं और सोचा, "ऐसा ही होता है। अच्छी लड़की ऐसी ही होती है, बिल्कुल मरीना जैसी।" उसके बाद, वे कहती हैं, कुछ भूला नहीं, बस ठहर गया, दफन हो गया। मुझे लगता है कि मन को लगा सदमा यही कर देता है।"

लैसरडा उन कई महिलाओं में हैं, जिनका एपस्टीन ने नाबालिग उम्र में यौन शोषण किया था। एपस्टीन अमेरिकी फाइनेंसर था, जो नाबालिग लड़कियों के शोषण का धंधा चलाता था। 2008 में, फ्लोरिडा की अदालत में उसने कबूला कि उसने एक नाबालिग को वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया था। उसे 13 महीने की सजा हुई। दोबारा उसे जुलाई 2019 में फ्लोरिडा और न्यूयॉर्क में बाल तस्करी के लिए संघीय कानून के तहत गिरफ्तार किया गया। मनैहट्टन जेल की कोठरी में 10 अगस्त 2019 को उसकी मौत हो गई, जिसे खुदकशी बताया गया।

लैसरडा कहती हैं, "मैं खुश थी, दुखी और गुस्से में थी, उलझन में थी। मैं सदमे में थी। मैं रोई।" 16 साल की उम्र में एपस्टीन के शोषण का शिकार हुई पीड़िता हेली रॉबसन उसकी मौत की खबर सुनकर खुद को संभाल नहीं पाई, "मैं बस जम-सी गई। मैं बिस्तर पर बैठकर रोती रही।"

उन्होंने आगे कहा, "जेफरी की मौत तो बस एक थी। मुझे नहीं लगता कि वह अकेले जिम्मेदार था।" उन्होंने कहा कि एपस्टीन की लंबे समय की साथी रहीं घिसलेन मैक्सवेल ने खास और अहम भूमिका निभाई। रॉबसन ने मैक्सवेल को "ड्रैगन की सरगना" बताया और आरोप लगाया कि वही एपस्टीन को "खिला-पिला कर पाल-पोस रही थी" और उसके लिए सारी व्यवस्थाएं करती थी। मैक्सवेल को 2020 में गिरफ्तार किया गया और 2021 में एपस्टीन के लिए नाबालिग लड़कियों की यौन तस्करी और उससे जुड़ी साजिश के आरोपों में दोषी ठहराया गया। उसे 2022 में 20 साल जेल की सजा सुनाई गई।

लैसरडा की तरह रॉबसन को भी "मसाज" के लिए बुलाया गया था, यह बताकर कि एपस्टीन नासा का वैज्ञानिक है तब वे 16 साल की थीं। उनके परिवार की माली हालत अच्छी नहीं थी और मां-बाप का सहारा नहीं था। उन्हें पैसे कमाने थे और खुद ही अपने को

संभालना भी था। वे 2002 में स्कूल से निकल रही थीं, तो एक आदमी उनके पास आया, जिसके साथ एक नाबालिग लड़की थी और उसने एक काम के लिए 200 डॉलर देने का वादा किया। इस तरह वे एपस्टीन के पाम बीच मेंशन पहुंची, जिसे "बिलियनेयर्स बीच" यानी अरबपतियों का ऐशगाह कहा जाता था। उस विला के अंदर नाबालिगों की नग्न तस्वीरें और मूर्तियां देखकर शुरू में वे हैरान रह गईं; उन्हें लगा कि तस्वीरें वहीं के बच्चों की हैं।

पहली मुलाकात जल्दी ही दु:स्वप्न में बदल गई, जो दशकों बाद भी उन्हें दहलाती रहती है। रॉबसन ने बताया कि शुरू में एपस्टीन ने प्यार-दुलार दिखाने की चालाकी दिखाई, और भरोसा दिलाने के लिए उसे "अच्छी लड़की" कहा। वे बताती हैं कि फिर उसने कहा कि यहां उसे "हर तरह से" आराम दिलाने के लिए लाया गया है। उन्होंने कहा, "मुझे आज 16 साल की लड़की की मनोदशा सोचकर काफी पछतावा है, जिसे लगा था कि वह हमदर्दी की दो-चार बातों से खुश हो गई थी, लेकिन वह कोरा छलावा था, मुझे तैयार करने का तरीका।" आखिरकार, दुराचार धौंस-धमकी में बदल गया: दूसरी लड़कियों को बहलाकर लाओ वरना बुरी गत हो जाएगी। उस धमकी के बाद रॉबसन ने कम से कम आठ लड़कियों को उससे मिलवाया।

लैसरडा ने याद किया कि कैसे उसने उसकी कमजोरी का फायदा उठाया। उसने कहा, "मुझे पता है कि तुम्हें पैसों की जरूरत है। मुझे पता है कि तुम मुश्किल वक्त से गुजर रही हो। मुझे पता है कि तुम यहां के बारे में किसी को बताने की जुर्रत नहीं कर सकती हो। तुम्हें मेरी जरूरत है।" फिर कहा कि कमाई जारी रखना चाहती हो तो दूसरी लड़कियां लाओ। लैसरडा बुरी तरह घिर चुकी थीं। उन्हें याद नहीं कि वे कितनी लड़कियों को ले आई थीं। "इस तरह मैं एपस्टीन की दुनिया में जुड़ गई।"

वह उनकी जिंदगी के लगभग हर हिस्से को कंट्रोल करता था। वह उन्हें शराब पीने या ड्रग्स लेने से मना करता था, और अगर उसे शक होता कि उन्होंने ऐसा किया है तो वह उनके बालों के स्ट्रैंड्स का टेस्ट करने की धमकी देता था। वह उन्हें कैब सर्विस इस्तेमाल करने से रोकता था क्योंकि वे रिकॉर्ड रखती थीं। बकौल उनके, इससे साफ है कि वह कहीं कोई निशान न छोड़ने को लेकर सतर्क था।

वह उन्हें इमोशनली भी मैनिपुलेट करता था। लड़कियों को एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा करता था, उनमें झगड़े लगाता था। वह किसी की तारीफ ''शानदार'' कहकर करता था या तुलना करता था कि कौन कितनी लड़कियां लाई, जिससे शोषण होड़ में बदल जाता था।

आप्रवासी होने के नाते लैसरडा को उस तरह

लड़ाई अब भी जारी

लगभग तीन दशकों से एपस्टीन के पीड़ित चुप्पी के बजाय बोलना चुन रहे हौं लेकिन उन्हें न्याय मिलना तो दूर, शुरू में न तो उनकी बात सुनी गई और न ही उन पर विश्वास किया गया। सबसे पहले सार्वजनिक मंच पर बोलने वालों में से वर्जीनिया रॉबर्ट्स गिफ्रे थीं, जिन्होंने 2011 में बताया था कि कैसे एपस्टीन और उसकी साथी घिसलेन मक्सिवेल ने नाबालिग उम्र में उनकी ट्रैफिकिंग की थी।

गिफ्रे ने कहा कि उन्हें वर्षों तक एपस्टीन के ''सेक्स स्लेव'' के तौर पर रहने के लिए मजबूर किया गया। न केवल एपस्टीन और मक्सिवेल ने बल्कि सियासत, बिजनेस, अकादमिक और शाही परिवारों के ताकतवर लोगों के साथ भी उन्हें सेक्स के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने बताया कि उन्हें अलग-अलग देशों में ले जाया गया, और डरा-धमकाकर चुप करा दिया गया। आखिरकार, वे भाग निकलीं और ऑस्ट्रेलिया में अपनी जिंदगी फिर शुरु की। उनकी हिम्मत ने दूसरों के लिए रास्ते खोल दिए। कई लोगों को खुलकर बोलने और शिकायत दर्ज कराने की हिम्मत दी गई। अप्रैल 2025 में, 41 साल की उम्र में उन्होंने खुदकशी कर ली। यह संकेत है कि सदमा कितने लंबे समय तक रहता है।

कोर्ट के दस्तावे जों में खौफनाक दास्तानें दर्ज हैं।4 नवंबर, 2010 को दिए गए बयान में बताया गया कि एपस्टीन ने2002 और 2005 के बीच फ्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच में अपने बंगले में ''चालीस से ज्यादा नाबालिग लड़कियों का बार-बार यौन शोषण किया।'' उनमें कई के साथ दर्जनों, यहां तक कि सैकड़ों बार कुकर्म काम किया गया। वेब सीरीज, जेफरी एपस्टीन: फिल्दी रिच में बताया गया है कि जांचकर्ताइसे 'मोलेस्टेशन पिरामिड स्कीम' कहते थे।

मनोवैज्ञानिक कैथरीन स्टैमौलिस के मुताबिक, डर के मारे कई चुप रहीं और फंसती चली गईं। स्टैमौलिस, न्यूयॉर्क में लाइसेंसशुदा मटेंल हल्थ काउंसलर हैं जिनकी विशषेज्ञता नाबालिग मनोविज्ञान में है। वे एपस्टीन के कई पीड़ितों के साथ काम कर रही हौं उन्होंने बताया कि शुरू में लड़कियों की कमजोरी जानने के लिए अच्छा बर्ताव करके उनका भरोसा जीता जाता था और फिर फंसा लिया जाता था। उन्होंने बताया कि एपस्टीन ''लोगों की अधूरी जरूरतों को ढूंढने और उनका फायदा उठाने मेंमाहिर था,'' वह ऐसे नाबालिगों की तलाश करता था जो पैसे की कमी से जूझ रही हों, अकेली हों, या कोई सहारा न हो।

एपस्टीन के पुराने कर्मचारी अल्फ्रेडो रोड्रिगेज ने बाद में जांचकर्ताओं को एक खास मोटा नोटबुक मुहैया कराया, जिसमें पूरे अमेरिका और विदेश, मिशिगन और कैलिफोर्निया से लेकर न्यूयॉर्क, न्यू मैक्सिको, वेस्ट पाम बीच और पेरिस तक की कई लड़कियों के नाम थे। इससे उसके व्याभिचार तंत्र के विशाल दायरे और पैमाने का पता चलता है।

एपस्टीन की 2019 की गिरफ्तारी से बहुत पहले, मारिया फार्मर जैसी महिलाओं ने 1996 में एफबीआइ में उसके बारेमेंशिकायत दर्ज कराई थी। उनकी बहन एनी फार्मर, सारा रैनसम और कई अन्य ने भी अधिकारियों को आगाह करने की कोशिश की थी। उन्होंने बदनाम करने की करतूतों, शमिर्दा करने और लगातार कानूनी धमकियों की परवाह नहीं की और डटी रहीं।

एपस्टीन की मौत के बाद भी इंसाफ अधूरा है। कैपिटल हिल पर प्रे स कॉन्फ्रेंस में तमाम पीड़ित एक साथ खड़ी हुईं और मांग की कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस सभी फाइलें जारी करे और कथित अपराधियों के नाम बताए। अमेरिका में रहने वाली टेक वकील और भारत में सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर की संस्थापक मिशी चौधरी जैसों की दलील है कि पूरी जानकारी देने का विकल्प पीड़ितों के पास ही रहना चाहिए था। उन्होंने कहा, "पीड़ितों को बोलने की आजादी चाहिए... बिना किसी डर या कलंक के।"

स्टैमॉलिस का यह भी कहना है कि अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का यह रवैया आला दर्जे की नाइंसाफी है कि "पीड़ितों के नाम तो सार्वजनिक हों लेकिन अपराधियों के नाम छिपा लिए जाएं। यह क्या दिखाता है कि पीड़ितों की पहचान दुराचार करने वालों की तुलना में कम सुरक्षा की हकदार है।"

एक सभा में पीड़ित लिसा फिलिप्स ने कहा, "सालोसाल बीत गए, लेकिन महिलाओं के लिए आगे बढ़ना आसान नहीं है। यह दौर तब तक खत्म नहीं होता जब तक हम यह न कहें कि खत्म हो गया है।"

लैसरडा ने भी यही कहा, "हमें उन सभी को सामने लाना होगा जिन अपराधियों के बारे में हम जानते हैं। हमें उन्हें इंसाफ के कटघरे में लाना होगा। उन्हेंकोर्ट में अपना दिन देखना होगा।" पीड़ितों के लिए मामला किसी एक आदमी का नहीं था, उसके केंद्र में ऐसा तंत्र था जिसने उसे ताकतवर बनाया। उनका कहना है कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है।आज सबसे जरूरी समाज और सत्तातंत्र में व्याप्त शोषण और दुरुपयोग का खुलासा है, ताकि ऐसे हैवान फिर न पनपें।

ट्रैफिकिंग का शिकार नहीं होना पड़ा, जैसा दूसरों को होना पड़ा। बकौल उनके, एक दिन एपस्टीन ने उन्हें एक दूसरी लड़की के साथ अपने बेडरूम में बुलाया, जो थोड़ा अजीब था, क्योंकि वहां कम ही बुलाया जाता था। वहां एक औरत को उसने अपना ''दोस्त'' बताया। लैसरडा को बाद में पता चला कि वह मक्सिवेल थी।

उन्होंने कहा, "उन दोनों ने हमारा रेप किया।" लैसरडा के साथ यह दुराचार लगभग तीन साल तक चलता रहा और बाद में वे वहां से निकल पाईं। एपस्टीन ने आखिरकार उन्हें जाने दिया क्योंकि वे उसके लिए "बहुत बड़ी" हो गई थीं। उन्हें याद आया कि एपस्टीन ने कहा था, "तुम अब मजेदार नहीं रही। तुम मरे लिए सही उम्र की लड़कियां नहीं लाती।" उसने उन पर 13 से 15 साल की लड़कियां लाने का दबाव डाला।

रॉबसन भी 2004 में 18 साल की हुईं तो बाहर निकल गईं। उन्होंने कहा, "मैं डरी हुई थी, लेकिन अब बहुत हो गया था।" डरते-डरते वे बाहर चली गईं। "मुझे एहसास हुआ कि मुझे यहां रहने की जरूरत नहीं है। मैं जा सकती हूं और जो भी नतीजे होंगे, उनसे निपट सकती हूं।" उन्होंने बताया कि 2006 में उनके बॉयफ्रेंड की हत्या कर दी गई।

उन्होंने कहा कि यह सदमा उनकी जिंदगी में बना रहा। उसके बाद वे एक बुरे रिश्ते मेंफंस गईं। प्रे ग्नेंट होने पर उनको मारा-पीटा गया। उन्होंने कहा, "मुझे कई बार पुलिस को फोन करना पड़ा। मुझे तलाक लेने मेंचार साल लग गए। मैं बहुत लकी हूं कि मैं उन कुछेक में से हूं, जो बच निकलीं।" आज, दोनों औरतें बेटियों की मां हैं और उनको ले कर काफी चिंतित रहती हौं परिवारों के साथ उनके रिश्ते तनावपूर्ण हैं, रॉबसन पूरी तरह से कटी हुई हौं

लैसरडा ने कहा, "मैं हर मां-बाप से कहती हूं कि अपने बच्चों को सीमाएं बतानी चाहिए। मसलन, तुम मुझसे ऐसे बात मत करो, तुम मुझे ऐसे मत छुओ, वगैरह।" वे बेटी की हरकतों पर नजर रखती हैं और फोन पर रोक लगाती हौं उन्होंने कहा, "इंटरनेट खतरनाक है।"

रॉबसन भी ऐसे ही नियम मानती हैं, सिर्फ दो भरोसेमंद परिवारों के साथ ही मिलने-जुलने की इजाजत देती हैं और अपनी बेटी की डिजिटल जिंदगी पर करीब से नजर रखती हौं जब वे पहली बार मां बनीं, तो उन्हें अक्सर बुरे सपने आते थे। "शुरुआत में मैं डरकर उठ बैठती थी, सपने मेंजे फरी चुपके से मेरे घर में घुसकर मेरी बेटी को बिस्तर से उठाकर ले जा रहा होता था।" ■

गैस के लिए हाहाकार

पश्चिम एशिया में युद्ध लंबा खिंचा (जिसकी पूरी संभावना है) और होरमुज जलडमरुमध्य का मार्ग बंद रहा, तो आने वाले दिनों में नोटबंदी या कोरोना काल जैसे परिमाण के संकट का सामना देश को करना पड़ सकता है।

रसोई गैस के लिए हाहाकार मच गया हो जगह-जगह से सिलिंडर भरवाने केलिए गै स एजेंसियों के सामने लंबी कतारों की खबरें मिल रही हों ये हाल तब है, जबकि सरकार ने एलपीजी की 80-85 फीसदी सप्लाई औद्योगिक क्षेत्र से घरेलू उपयोग के लिए भेजने का निर्णय लिया हो कॉमर्शियल उपयोग के लिए गैस की सप्लाई काफी हद तक बाधित हो चुकी हो गौरतलब है कि अभी संकट के शुरुआती दिन हों पश्चिम एशिया में युद्ध लंबा खिंचा (जिसकी पूरी संभावना हो) और होरमुज जलडमरुमध्य का मार्ग बंद रहा, तो आने वाले दिनों में नोटबंदी या कोरोना काल जैसे परिमाण के संकट का सामना देश को करना पड़ सकता हो अब यह सामने आया है कि चूंकि गैस का भंडारण मंहगा पड़ता है, इसलिए भारत ने खुद को लगातार सप्लाई पर ही निर्भर बनाए रखा। अब चूंकि मुश्किल आ खड़ी हुई है, तो सरकार आपातकालीन निर्णय लेने को मजूबर हो उसने ऐसे लिए हैं, जिनसे घरेल उपभोक्ताओं को अधिकतम राहत मिल सके। यह सही, मगर समस्याग्रस्त प्राथमिकता हो आखिर श्रमिक वर्ग के लोग फैक्टरियों या कार्यस्थलों पर कैंटीन या ढाबों में भोजन करतेहैं।

लाइन होटल ट्रक एवं बस ड्राइवरों और अन्य लंबी दूरी के यात्रियों के खाना खाने की जगहें हों फिर अनगिनत लोग रोज कामकाज के सिलसिले में यात्राओं पर जाते हैं, जो रेस्तरां या होटलों में ही भोजन करते हों फिलहाल स्थिति यह है कि अनेक शहरों से रेस्तरां और होटलों में मनू की कटौती हो रही है और कुछ रोज में उनके बंद हो जाने की चेतावनी दी गई हो रेस्तरां और क्लाउड किचन पर लाखों कर्मचारी एवं होम फूड डिलीवरी से जुड़े गिग वर्कर निर्भर हैं।उधर औद्योगिक गै स की कटौती से कल-कारखाने बंद हुए, तो उसका असर लाखों नौकरीशुदा लोगों पर पड़ेगा। उत्पादन, वितरण, एवं उपभोग में गिरावट से अर्थव्यवस्था पर होने वाला दूरगामी असर अलग हो तो कुल मिलाकर देश एक बड़ी मुश्किल में फंसता नजर आ रहा हो इसके मद्देनजर क्या यह कहना काफी होगा कि युद्ध होता है, तो दिक्कत होती है? या एहतियाती कदम ना उठाने केलिए किसी की जवाबदेही तय होगी ? ■

महिलाओं की भागीदारी से ही सशक्त होगा राष्ट्र

हजारों मील की यात्रा भी एक पहले कदम से शुरू होती है। सही मायने में महिला दिवस तब सार्थक होगा जब असलियत में महिलाओं को वह सम्मान मिलेगा जिसकी वे हकदार हैं। समाज को संकल्प लेना चाहिए कि भारत में समरसता की बयार बहे, किसी घर में कन्या भ्रूण हत्या न हो और किसी भी बेटी को दहेज के नाम पर न जलाया जाए।

-ब्यूरो डेस्क

हम विश्व में लगातार कई वर्षों से अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाते आ रहे हैं महिलाओं के सम्मान के लिए घोषित इस दिन का उद्देश्य सिर्फ महिलाओं के प्रति श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करना है इसलिए इस दिन को महिलाओं की आध्यात्मिक, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उपलब्धियों के उपलक्ष्य में मनाया जाता है नारी मानव जाति के लिए जननी का रूप है कहा जाए तो जननी ही नारी है और नारी ही जननी है नारी शक्ति या मातृशक्ति का इस संसार को आगे बढ़ाने मेंअहम योगदान है बिना नारी के इस दुनिया की कल्पना नहीं की जा सकती। अगर नारी नहीं होगी तो इस संसार का विकास नहीं हो पाएगा। नारी ही एक पुरुष को जन्म देती है, तभी नारी की सहन करने की शक्ति यानी सहनशक्ति का अहसास होता है कि वह इस संसार में कितनी मजबूत शक्ति है

आज उसी मजबूत नारी शक्ति पर कुछ मानसिक रूप से विक्षिप्त पुरुषों (ऐसे पुरुष जो नारी शक्ति को अपने उपभोग की वस्तु समझते हैं)द्वारा बलात्कार जैसी घटनाएं होती हैं ऐसे पुरुषों द्वारा नारी को शारीरिक शोषण द्वारा हमेशा लज्जित किया जाता है, यह चीज़ समस्त मानवजाति को शर्मसार करती है कुछ पुरुषों के ऐसे कृत्यों द्वारा बाकी के साफ-सुथरी छवि के पुरुषों को भी शर्मसार होना पड़ता है आज ज़रूरत है महिलाओं और छोटी-छोटी बच्चियों के खिलाफ होने वाली बलात्कार जैसी घटनाओं पर लगाम लगाई जाए। यह तभी हो सकता है जब बलात्कार जैसे कृत्यों के खिलाफ मानव जाति एकजुट होकर फैसला ले और जो लोग दोषी पुरुषों का साथ देते हैं, ऐसे लोगों का भी समाज पूर्ण रूप से बहिष्कार करे। इसके साथ ही आज ज़रूरत है कि बलात्कार जैसे कृत्यों के खिलाफ सरकारें कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान करें और

बलात्कार जैसे मामलों की फास्टट्रैक कोर्ट द्वारा त्वरित कार्यवाही हो, जिससे कि दूसरे लोग भी ऐसा कृत्य करने से पहले सौ बार सोचें तभी मानव जाति और समाज के स्तर को उठाया जा सकता है।

आज अपने समाज में नारी के स्तर को उठाने के लिए सबसे ज्यादा ज़रूरत है महिला सशक्तिकरण की। महिला सशक्तिकरण का अर्थ हैमहिलाओं की आध्यात्मिक, शैक्षिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक शक्ति में वृद्धि करना; बिना इसके महिला सशक्तिकरण असंभव है। आज हर महिला समाज में धार्मिक रूढ़ियों और पुराने नियम-कानूनों में अपने आप को बंधा पाती है। पर अब वक्त है कि हर महिला तमाम रूढ़ियों से खुद को मुक्त करे। प्रकृति ने औरतों को खूबसूरती ही नहीं, दृढ़ता भी दी है। प्रजनन क्षमता भी सिर्फ उसी को हासिल है। भारतीय समाज में आज भी कन्या भ्रूण हत्या जैसे कृत्य दिन-रात किए जा रहे हैं। पर हर कन्या में एक मां दुर्गा छिपी होती है। यह हैरत की बात है कि दुर्गा की पूजा करने वाला इंसान दुर्गा की प्रतिरूप नवजात कन्या का गर्भ में वध कर देता है। इसमें पिता और परिवार के साथ समाज भी सहयोग देता है।

आज ज़रूरत है कि देश मेंबच्चियों को हम वही आत्मविश्वास और हिम्मत दें जो लड़कों को देते हैं। इससे प्रकृति का संतुलन बना रहे। इसलिए ज़रूरी है कि इस धरती पर कन्या को भी बराबर का सम्मान मिले और उसकी गरिमा भी बनी रहे। अपनी अंदरूनी शक्ति को जाग्रत करें और हर स्त्री में यह शक्ति जगाएं ताकि वह हर विकृत मानसिकता का सामना पूरे साहस और धीरज के साथ कर सके। एक नारी के बिना किसी भी व्यक्ति का जीवन सृजित नहीं हो सकता है। जिस परिवार में महिला नहीं होती, वहां पुरुष न तो अच्छी तरह से जिम्मेदारी निभा पाते हैंऔर न ही लंबे समय तक जीते हैं।वहीं जिन परिवारों में महिलाओं पर परिवार की जिम्मेदारी होती है, वहां महिलाएं हर चुनौती और हर जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से निभाती हैं और परिवार खुशहाल रहता है।

अगर मजबूती की बात की जाए तो महिलाएं पुरुषों से ज्यादा मजबूत होती हैं क्योंकि वे पुरुषों को जन्म देती हैं। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के अंतर्गत सभी को अनुच्छेद 14-18 के तहत समानता का अधिकार दिया गया है, जो महिलाओं और पुरुषों को बराबरी का अधिकार देता है। इसके अंतर्गत यह भी सुनिश्चित किया गया

है कि राज्य के तहत होने वाली नियुक्तियों और रोजगार के संबंध में किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा।

देश मेंमहिलाओं के उत्थान और सशक्तिकरण को देखते हुए हमारे संविधान को 1993 में संशोधित किया गया। 73वें संशोधन के ज़रिए संविधान में अनुच्छेद 243A से 243O तक जोड़ा गया। इस संशोधन में यह व्यवस्था की गई कि पंचायतों और नगरपालिकाओं में कुल सीटों की एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए सुरक्षित होंगी। साथ ही कम से कम एक-तिहाई चेयरपर्सन की सीटें भी महिलाओं के लिए आरक्षित की गईं। पंचायती राज संस्थानों में 33 प्रतिशत आरक्षण लागू होने से महिलाओं के प्रतिनिधित्व में तेजी से वृद्धि हुई है। वास्तव में देखा जाए तो देशभर में पंचायतों में चुनी गई महिलाओं का प्रतिनिधित्व अब 40 प्रतिशत तक हो गया है और कुछ राज्यों में तो यह 50 प्रतिशत तक पहुंच गया है। बिना प्रतिनिधित्व के महिलाओं का सशक्तिकरण असंभव है।

नए संसद भवन में 20 सितंबर 2023 को 'नारी शक्ति वंदन विधेयक' लोकसभा में पास हुआ था। राज्यसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इसे अपनी मंजूरी दे दी है। इस अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान है। आने वाले सालों में इस कानून के लागू होने के बाद राजनीतिक परिदृश्य बहुत बदल जाएगा। हालांकि, इस अधिनियम की एक चर्चा यह भी है कि इसके अंतर्गत पिछड़े और आदिवासी वर्ग की महिलाओं को अलग से कोटा नहीं दिया गया है। यदि भविष्य में सरकार पिछड़े और दबे-कुचले वर्ग की महिलाओं के लिए विशेष कोटे की व्यवस्था करती है, तो उनका प्रतिनिधित्व और अधिक सशक्त हो पाएगा। कोई भी राष्ट्र महिलाओं के बिना शक्तिहीन है, क्योंकि राष्ट्र को हमेशा महिलाओं से ही शक्ति मिलती है। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी से लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होती हैं।

आज ज़रूरत है कि समाज में महिलाओं को अज्ञानता, अशिक्षा, कूपमंडूकता, संकुचित विचारों और रूढ़िवादी भावनाओं के गर्त से निकालकर प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए उन्हें आधुनिक घटनाओं, ऐतिहासिक गरिमामयी जानकारी और सामाजिक क्रियाकलापों से अवगत कराया जाए। उनमें आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक और राजनीतिक चेतना पैदा की जाए जिससे नारी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर समाज को आगे बढ़ाने मेंसहयोग कर सके। हमें हठधर्मिता त्याग कर शैक्षिक, सामाजिक, सौहार्दपूर्ण और व्यावसायिक मार्ग प्रशस्त करते हुए महिलाओं के सामाजिक उत्थान का संकल्प लेना चाहिए।

हजारों मील की यात्रा भी एक पहले कदम से शुरू होती है। सही मायने मेंमहिला दिवस तब सार्थक होगा जब असलियत में महिलाओं को वह सम्मान मिलेगा जिसकी वे हकदार हैं। समाज को संकल्प लेना चाहिए कि भारत में समरसता की बयार बहे, किसी घर में कन्या भ्रूण हत्या न हो और किसी भी बेटी को दहेज केनाम पर न जलाया जाए। विश्व के मानस पटल पर एक अखंड और प्रखर भारत की तस्वीर तभी प्रकट होगी जब हमारी मातृशक्ति अपने अधिकारों और शक्ति को पहचान कर अपनी गरिमा और गौरव का परिचय देंगी और राष्ट्र निर्माण में अपनी प्रमुख भूमिका निभाएगी। ■

दिलों की रानी

प्रियंका चोपड़ा जोनस के इस अजीब फैशन स्टेटमटें से बाहर, सनफ्लावर यलो गाउन की असली कीमत मॉडल जीना संधू को पता हौ द ब्लफ फिल्म के प्रीमियर पर पहुंची प्रियंका से जीना का आमना-सामना हुआ और बात करते-करते जीना इतनी भावुक हो गई कि आंसू निकल पड़े। प्रियंका ने बिना एक भी पल गंवाए अपने गाउन से जीना के आंसू पोंछ दिए। बस फिर क्या था, शब्द बदल गए, जज्बात बदल गए। ■

Zental Media House

Add-Hazratganj Lucknow

मैगजीन, न्यूजपेपर

कम्पोजिंग और न्यूज पोर्टल अपडेट
कराने के लिए सम्पर्क करें।

शुभम यादव

8881544447

डिजिटल प्रिंटिंग | ऑफसेट प्रिंटिंग | ऑल टाइप प्रिंटिंग सुविधाएं उपलब्ध।

तेजस INSTITUTE OF PROFESSIONAL STUDIES

LATERA, DUMARIYAGANJ, SIDDHARTH NAGAR (U.P.)

COURSES

UGC, AICTE Approved

B.A., B.com, M.A., M.S.W., NTT, PTT

IGD Bombay Art (By Maharastra Govt.)

CCC, BCC, 'O' Level (By Nielit पूर्व में DOEACC)